

इस अंक में

- भारत-आसियान आर्थिक संबंधों की गतिशीलता का परिदृश्य
- भारत की लिथियम आवश्यकताएं पूरी करना
- भारत से मोटे अनाजों का उत्पादन और निर्यात बढ़ाना
- भारत में इस्पात उद्योग
- स्थानीय श्रम बाजार पर अप्रवासियों और उनके प्रभाव पर निबंध

संपादकीय टीम:

श्री डेविड सिनाटे, मुख्य महाप्रबंधक
श्री विश्वनाथ जांध्याला, सहा. महाप्रबंधक
सुश्री अल्फिया अंसारी, उप प्रबंधक



की तिमाही प्रकाशन

केन्द्र एक भवन, 21 वीं मंज़िल,
विश्व व्यापार केन्द्र संकुल,
कफ़ परेड, मुंबई - 400 005.
फोन: 022 2217 2600
ईमेल: ccg@eximbankindia.in
www.eximbankindia.in
www.eximmitra.in



भारत-आसियान आर्थिक संबंधों की गतिशीलता का परिदृश्य

- सिद्धार्थ नेमा, उप प्रबंधक
धितीका शाह, अधिकारी

प्रस्तावना

दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन (आसियान) अपनी भौगोलिक स्थिति और विपुल प्राकृतिक संसाधनों के लिए जाना जाता है और दुनिया के प्रमुख क्षेत्रीय संगठनों में से एक है। इसकी स्थापना आसियान घोषणा (बैंकॉक घोषणा) पर हस्ताक्षर के साथ 08 अगस्त, 1967 को हुई थी। आसियान के संस्थापक सदस्यों में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपींस, सिंगापुर और थाईलैंड शामिल हैं। 07 जनवरी, 1984 को ब्रुनेई दारुस्सलाम आसियान में शामिल हुआ। उसके बाद 28 जुलाई, 1995 को वियतनाम, 23 जुलाई, 1997 को लाओ पीडीआर और म्यांमार एवं 30 अप्रैल, 1999 को कंबोडिया के इसमें शामिल होने से इसकी सदस्यों की संख्या 10 हो गई।

पिछले पांच दशकों में आसियान की अर्थव्यवस्था में अच्छी वृद्धि दर्ज की गई। 2023 में इसका कुल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 3.9 ट्रिलियन यूएस डॉलर आंका गया। यह 1999 के 607.3 बिलियन यूएस डॉलर के मुकाबले छह गुना से भी अधिक रहा, जब पहली बार आसियान सदस्यों की संख्या 10 हुई थी। वर्ष 2022 में आसियान का संयुक्त जीडीपी इतना था कि यदि एकल अर्थव्यवस्था के रूप में देखा जाए तो यह दुनिया में पांचवीं सबसे बड़ी और एशिया में चीन तथा जापान के बाद तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रही। आज यह क्षेत्र एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र है और वैश्विक मूल्य शृंखलाओं (जीवीसी) में एक प्रमुख संगठन के रूप में उभरा है।

आसियान का रणनीतिक महत्त्व इसलिए भी है क्योंकि आसियान देश एशिया-प्रशांत और हिंद महासागर क्षेत्र के भौगोलिक रूप से महत्वपूर्ण मिलन-बिंदुओं पर स्थित हैं, जो आसियान को क्षेत्रीय और वैश्विक शक्तियों, दोनों के लिए एक केंद्र बिंदु बनाते हैं। हिन्द महासागर क्षेत्र और प्रशांत महासागर क्षेत्र को आसियान द्वारा केवल निकटस्थ प्रादेशिक स्थान नहीं माना जाता है, बल्कि घनिष्ठ रूप से एकीकृत और परस्पर जुड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है, जिसमें आसियान की केंद्रीय और रणनीतिक भूमिका है। इसी के परिणामस्वरूप भारत-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत-प्रशांत आसियान संभावनाएं जैसी पहल की गई।

भारत और आसियान: व्यापार संबंध

भारत-आसियान संबंधों का महत्त्व बहुआयामी है। इसमें राजनीतिक, आर्थिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक पहलू शामिल हैं। भारत के आर्थिक विकास में आसियान क्षेत्र के महत्त्व को समझते हुए भारत ने अपनी 'लुक ईस्ट एशिया' नीति के माध्यम से इस क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया है।

भारत ने अक्टूबर 2003 में आसियान के साथ व्यापक आर्थिक सहयोग संबंधी फ्रेमवर्क करार पर हस्ताक्षर किए थे। छह वर्षों की वार्ता के बाद भारत ने 13 सितंबर, 2009 को आसियान के साथ मुक्त व्यापार करार (एफटीए) पर हस्ताक्षर किए, जो 01 जनवरी, 2010 से प्रभावी हुआ।

भारत और आसियान के बीच मौजूदा मुक्त व्यापार करार के तीन पहलू हैं- वस्तु व्यापार; सेवा व्यापार; और निवेश। यद्यपि एआईएफटीए के अंतर्गत प्रतिबंधित सूचियां बाजार पहुंच में सुधार लाने की दृष्टि से वार्षिक टैरिफ समीक्षा के अध्यक्षीन हैं, फिर भी कृषि, वस्त्र, मशीनरी, ऑटोमोबाइल, रसायन और प्लास्टिक जैसे क्षेत्रों से संबंधित 489 टैरिफ लाइनें नकारात्मक सूची के अंतर्गत सूचीबद्ध हैं।

हाल के वर्षों में, आसियान भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदारों में से एक बन गया है। भारत और आसियान का कुल व्यापार वर्ष 2013 के 80.2 बिलियन यूएस डॉलर से वर्ष 2022 में बढ़कर 133.4 बिलियन यूएस डॉलर का हो गया, जो अब वर्ष में भारत के कुल वैश्विक व्यापार का 11.3% हिस्सा है। कुल मिलाकर इस अवधि के दौरान आसियान के साथ भारत का कुल व्यापार 5.2% की सीएजीआर से बढ़ा है। इस क्षेत्र में भारत का निर्यात 1.5% की सीएजीआर से बढ़ा, जबकि आसियान से इसके आयात में 7.8% की उच्चतर सीएजीआर दर्ज की गई।

वर्ष 2013 और 2022 के प्रमुख निर्यातों में खनिज ईंधन और तेल भारत से शीर्ष निर्यात उत्पाद रहे। तथापि, इनका निर्यात 2013 के 29.3% से घटकर 2022 में 25.1% रह गया। अन्य प्रमुख निर्यात उत्पादों में मशीनरी और यांत्रिक उपकरण (भारत के कुल निर्यात का 8.2%), प्राकृतिक या कृत्रिम मोती, कीमती या अर्द्ध-कीमती रत्न (6.4%) और कार्बनिक रसायन (4.5%) शामिल रहे। इसी तरह, खनिज ईंधन और तेल आसियान से भारत के शीर्ष आयातित उत्पाद भी बने रहे और आसियान से कुल भारतीय आयात वर्ष 2013 के 24.3% से काफी हद तक अपरिवर्तित रहते हुए 2022 में 24.5% रहे।

आसियान-भारत द्विपक्षीय निवेश

इस क्षेत्र के साथ भारत के निवेश संबंधों की बात की जाए तो आसियान अर्थव्यवस्थाओं में सर्वाधिक निवेश सिंगापुर का है। आसियान से भारत

के कुल एफडीआई प्रवाह के लगभग 98% हिस्से के साथ सिंगापुर भारत में प्रमुख निवेशक बना हुआ है। उसके बाद थाईलैंड (0.8%) और मलेशिया (0.8%) का स्थान है। भारत में आसियान का एफडीआई प्रवाह मुख्यतः रियल एस्टेट क्षेत्र में रहा है, जिसमें आसियान से भारत के कुल एफडीआई प्रवाह का 26.1% हिस्सा रहा। इसके बाद अक्षय ऊर्जा (18.1%), कोयला, तेल और गैस (12%), संचार (10.5%), सेमीकंडक्टर (10.4%) और रसायन (5.5%) क्षेत्र का हिस्सा रहा।

एफडीआई जावक प्रवाह के संदर्भ में भी सिंगापुर भारत का प्रमुख गंतव्य है। आसियान में भारत के कुल एफडीआई जावक में 93.2% हिस्सा सिंगापुर का है। इसके बाद इंडोनेशिया (1.7%), मलेशिया (1.6%) और फिलीपींस (1%) का हिस्सा रहा। भारत का अधिकांश एफडीआई जावक प्रवाह कोयला, तेल और गैस क्षेत्र में रहा, जो आसियान को भारत के कुल एफडीआई जावक प्रवाह का 27.2% रहा। इसके बाद व्यावसायिक सेवाएं (10.9%), सॉफ्टवेयर और आईटी सेवाएं (8.9%), रबर (8.7%) और परिवहन एवं भंडारण (8.1%) का हिस्सा रहा।

भारत-आसियान द्विपक्षीय व्यापार में बाधाएं

एआईएफटीए के क्रियान्वयन के बाद, आसियान से भारत का आयात वर्ष 2010 के 29.6 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 2022 में 89.3 बिलियन यूएस डॉलर का हो गया, जिसमें 201.7% की चौकाने वाली वृद्धि दर्ज की गई। फलस्वरूप, आसियान के साथ भारत का व्यापार घाटा 2010 के मामूली 6.6 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 2022 में 45.3 बिलियन यूएस डॉलर का हो गया, जिसमें छह गुना से अधिक वृद्धि दर्ज की गई।

एआईएफटीए में दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तावित टैरिफ कटौती में असंतुलन के अलावा विवाद का अन्य प्रमुख बिंदु उत्पत्ति के कठोर नियम (आरओओ) विनियम और गैर टैरिफ उपायों (एनटीएमएस) की बढ़ती संख्या रहा है।

आसियान के लिए चीन और कोरिया दो शीर्ष आयात स्रोत रहे। वर्ष 2022 में 601.7 बिलियन यूएस डॉलर के आयात के साथ आसियान के कुल आयात में लगभग 32% हिस्सेदारी इन्हीं दोनों की रही। आसियान का चीन और दक्षिण कोरिया, दोनों के साथ मुक्त व्यापार करार (एफटीए) है, जो 2010 में लागू हुआ था। एफटीए के प्रभावी होने के बाद चीन से आसियान का वस्तु आयात 2010 के 126.7 बिलियन यूएस डॉलर से 2022 में 263.8% बढ़कर 460 बिलियन यूएस डॉलर का हो गया। दक्षिण कोरिया के मामले में भी आसियान का आयात 2010 के 57 बिलियन यूएस डॉलर से 146.2% बढ़कर 2022 में 140.8 बिलियन यूएस डॉलर का हो गया।

तथापि, एफटीए के कार्यान्वयन के बाद के वर्षों में चीन और दक्षिण कोरिया की तुलना में भारत के साथ आसियान के व्यापार घाटे का स्तर अधिक महत्व रखता है। पूर्व में उल्लिखित अनुसार, एआईएफटीए एकत्रीकरण के साथ भारत वस्तुओं का निवल आयातक बना हुआ है। पिछले दस वर्षों के दौरान व्यापार घाटा लगातार बढ़ा है। यह 2013 के 4.4 बिलियन यूएस डॉलर से 2022 में बढ़कर 45.3 बिलियन यूएस डॉलर का हो गया। दूसरी ओर, व्यापार संतुलन काफी हद तक आसियान के भागीदार देशों के पक्ष में रहा है, जिसमें चीन और दक्षिण कोरिया ने 2022 में क्रमशः 139.6 बिलियन यूएस डॉलर और 57.6 बिलियन यूएस डॉलर का अधिशेष दर्ज किया।

सिंगापुर, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया आसियान में पांच प्रमुख आयातक देश हैं, जिनकी इस संगठन के कुल आयात में 76.2% हिस्सेदारी है। इनमें से सिंगापुर की व्यापार व्यवस्था उदार है, जिसके आयातों पर नगण्य टैरिफ दरें लगाई जाती हैं। भारत, चीन और दक्षिण कोरिया द्वारा वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया को निर्यात किए जाने वाले उत्पादों पर लागू प्रभावी टैरिफ दरों के सामान्य औसत (एचएस) के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि व्यापार की गई वस्तुओं में चीन और दक्षिण कोरिया के मामले में टैरिफ उन्मूलन के तहत टैरिफ लाइनों की संख्या, भारत की तुलना में काफी अधिक है। उदाहरण के लिए शुल्क मुक्त आयात वाले उत्पादों की 1,610 श्रेणियां (6-अंकों के एचएस कोड पर) हैं, जिनमें 0% की एचएस दर वाली 3,185 टैरिफ लाइनें हैं, जिनमें 2020 में कुल आयात 2,992.1 मिलियन यूएस डॉलर के रहे। यह 2020 में भारत से वियतनाम के कुल आयात के 66.8% से अधिक है। तथापि, दक्षिण कोरिया के मामले में उत्पादों की 3,100 श्रेणियां हैं, जिनके अंतर्गत 6,131 टैरिफ लाइनें, जिनमें शुल्क मुक्त आयात किया जाता है। आयात उत्पादों की इस श्रेणी में 2020 में 41,805.3 मिलियन यूएस डॉलर का आयात रहा, जो उस वर्ष दक्षिण कोरिया से वियतनाम के कुल आयात के 89.2% से अधिक है।

निष्कर्ष

भौगोलिक संपर्क के संदर्भ में आसियान और भारत के बीच और अधिक एकीकरण की आवश्यकता है। आसियान-भारत साझेदारी को और सुदृढ़ करने का आधार भौतिक, संस्थागत, डिजिटल और सांस्कृतिक रूप से संपर्क बढ़ाना है। बेहतर संपर्क वस्तुओं के साथ-साथ लोगों के आवागमन के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा।

सितंबर 2023 में संपन्न 20वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन के दौरान माननीय प्रधानमंत्री द्वारा भारत-आसियान सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत के 12-सूत्री प्रस्ताव के तहत भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया गया। माननीय प्रधानमंत्री ने दक्षिण-पूर्व एशिया-भारत-पश्चिम एशिया-यूरोप (एसईआईडब्ल्यूईसी) को जोड़ने वाले मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी और आर्थिक गलियारे की स्थापना के बारे में उल्लेख किया था।

10 आसियान देशों में से मलेशिया, म्यांमार, सिंगापुर, वियतनाम और थाईलैंड के साथ भारत का सीधा हवाई संपर्क है, जबकि कंबोडिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस सहित अन्य पांच देशों के लिए भारत से सीधी फ्लाइट नहीं है। आसियान के साथ भारत का बड़ा व्यापार और पर्यटन संबंध है। व्यापार और पर्यटन में सहयोग के माध्यम से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को सुदृढ़ करने में इन देशों से सीधा हवाई संपर्क सहायक होगा।

हाल ही में संपन्न भारत-आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने आसियान भागीदारों के साथ भारत के डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) स्टैक को साझा करने की पेशकश की। कोविड के समय शुरू हुए दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम के प्रबंधन में भारत की अनूठी डीपीआई पहलों ने महामारी की अस्त-ब्यस्तता के बीच डिजिटल क्रांति ला दी। डिजिटल आईडी (आधार) और भुगतान अवसंरचना (यूपीआई) जैसी भारत की स्वदेशी पहलों का उल्लेख जी-20 के अंतर्गत डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्य समूह (डीईडब्ल्यूजी) द्वारा भी किया गया।

आसियान और भारत में पारस्परिक रूप से लाभकारी प्रौद्योगिकी साझेदारी स्थापित करने की अपार संभावनाएं हैं। एक तरफ आसियान यूपीआई, जन धन, आधार, ओएनडीसी और कोविन सहित समावेशी और सस्टेनेबल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के भारत के सफल कार्यान्वयन से लाभान्वित हो सकता है, तो वहीं दूसरी ओर भारत के भुगतान इंटरफेस की सार्वभौमिकता विकसित होने से भारत भी लाभान्वित होगा, जिससे व्यापार के साथ-साथ धन-प्रेषण के संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय ट्रांजैक्शन सुगम होंगे। ब्लॉक स्तर पर डिजिटल अवसंरचना के व्यापक एकीकरण से व्यापार सुगम होगा और बाधाएं दूर होंगी।

इसके अलावा, भारत के तुलनात्मक लाभ के आधार पर आसियान क्षेत्र के साथ व्यापार बढ़ाना भारत के लिए आकस्मिक है। एआईएफटीए की आगामी समीक्षा में अधिक रियायतें प्राप्त करने की आवश्यकता है, जिसमें भारत की बढ़ती जरूरतों और उभरते घरेलू बाजार पर विशेष जोर दिया जाएगा। ■

भारत की लिथियम आवश्यकताएं पूरी करना

- सृजिता नंदी, उप प्रबंधक
सिद्धार्थ नेमा, उप प्रबंधक

भारत में तेजी से बढ़ते औद्योगीकरण, बढ़ती आबादी एवं ऊर्जा मांगों के चलते संपोषी और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों पर उल्लेखनीय रूप से बल दिया जा रहा है। पूरी दुनिया अक्षय ऊर्जा और परिवहन के विद्युतीकरण की ओर बढ़ रही है। परिवहन के विद्युतीकरण में लिथियम-आयन बैटरी एक प्रमुख घटक है। इसलिए लिथियम का महत्व भी बढ़ गया है। दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम भंडार अर्जेंटीना, बोलिविया और चिली में है, जिसे लिथियम त्रिकोण कहा जाता है। यह लिथियम उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में उभरा है।

लिथियम त्रिकोण का व्यापक आर्थिक परिदृश्य और विदेश व्यापार

वर्ष 2022 में 630 बिलियन यूएस डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद के साथ लैटिन अमेरिकी और कैरिबियाई (एलएसी) क्षेत्र में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अर्जेंटीना की रही। इस क्षेत्र में इसी अवधि के दौरान 310 बिलियन यूएस डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद के साथ चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था चिली की रही, जबकि बंदरगाहविहीन देश बोलिविया का सकल घरेलू उत्पाद 43.4 बिलियन यूएस डॉलर रहा।

दुनिया के अन्य देशों के साथ लिथियम त्रिकोण क्षेत्र का मर्चेडाइज व्यापार 2021 में 349.7 बिलियन यूएस डॉलर का रहा, जिसमें असाधारण रूप में 44.1% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2021 में 181.8 बिलियन यूएस डॉलर का निर्यात रहा, जबकि 167.9 बिलियन यूएस डॉलर का आयात रहा। परिणामस्वरूप, इस क्षेत्र के लिए 13.9 बिलियन यूएस डॉलर का व्यापार अधिशेष रहा।

भारत-लिथियम त्रिकोण द्विपक्षीय व्यापार संबंध

बीते दशक में लिथियम त्रिकोण के साथ भारत के व्यापार में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई है। इसके साथ भारत का कुल व्यापार वर्ष 2012 के 4.9 बिलियन यूएस डॉलर से वर्ष 2021 में लगभग दोगुना बढ़कर 9.6 बिलियन यूएस डॉलर का हो गया। वर्ष 2021 में भारत से लिथियम त्रिकोण को निर्यात 2.5 बिलियन यूएस डॉलर के करीब था, जो 2020 से 56% अधिक रहा, जबकि आयात 7.2 बिलियन यूएस डॉलर का रहा, जो गत वर्ष से 59% अधिक रहा।

भारत पिछले दशक में लिथियम त्रिकोण के निर्यातों के लिए आयातों और बाजार के एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा है। अर्जेंटीना, बोलिविया और चिली के साथ-साथ एलएसी क्षेत्र भारत के समग्र व्यापार के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। भारत के कुल निर्यात का 13% हिस्सा इस क्षेत्र को निर्यात होता है, जबकि भारत को इस क्षेत्र के कुल निर्यात का हिस्सा 29.5% है, जो भारत और लिथियम त्रिकोण के बीच फलते-फूलते आर्थिक संबंधों के संकेत हैं।

लिथियम त्रिकोण को भारत का निर्यात काफी विविधतापूर्ण है। भारत से लिथियम त्रिकोण के शीर्ष निर्यातों में अन्य के साथ-साथ परिवहन वाहन, खनिज ईंधन और तेल, फार्मासूटिकल उत्पाद और कार्बनिक रसायन शामिल हैं।

वैश्विक लिथियम परिदृश्य

यूएस भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार दुनिया भर में निरंतर अन्वेषण के परिणामस्वरूप, लिथियम के वैश्विक संसाधन 2021 के 89 मिलियन टन से 2022 में 10% बढ़कर 98 मिलियन टन हो गए। दक्षिण अमेरिका की एंडीज पर्वत शृंखलाओं में महाद्विपीय ब्राउन एक्वीफर्स अधिक ऊंचाई पर स्थित लिथियम समृद्ध ब्राइन का सबसे विपुल स्रोत है। अर्जेंटीना, बोलिविया और चिली में केंद्रित सालार (साल्ट फ्लैट्स) को सामूहिक रूप से लिथियम त्रिकोण के रूप में जाना जाता है, जो वैश्विक लिथियम संसाधनों का लगभग 53.1% है। अर्जेंटीना में सालार डी मुर्टो होम्ब्रे, सालार डी ओलारोज और सालार डी मारियाना सहित उच्च लिथियम भंडार वाले कई सालार हैं और वैश्विक लिथियम संसाधनों का 20% हैं। बोलिविया का सालार डी उयूनी दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम भंडार है। दुनिया के कुल लिथियम संसाधनों के 21% संसाधन बोलिविया के हैं। चिली का सालार डी अटाकामा दुनिया में ब्राइन से लिथियम उत्पादन का फिलहाल सबसे बड़ा स्रोत है।

वैश्विक लिथियम भंडार वर्ष 2021 के 22 मिलियन टन से बढ़कर वर्ष 2022 में 26 मिलियन टन हो गया। लिथियम के वैश्विक भंडार में 35.8% हिस्से के साथ सबसे बड़ी हिस्सेदारी चिली की रही। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया (23.8%), अर्जेंटीना (10.4%) और चीन का (7.7%) स्थान रहा। वर्ष 2022 में ऑस्ट्रेलिया 46.9% की हिस्सेदारी के साथ लिथियम का सबसे बड़ा उत्पादक रहा। उसके बाद चिली (30%), चीन (14.6%) और अर्जेंटीना (4.8%) का स्थान रहा।

वर्ष 2022 में लिथियम की वैश्विक खपत 134,000 टन दर्ज की गई, जो 2021 की तुलना में 44.1% अधिक रही। लिथियम का सबसे अधिक उपयोग बैटरी में (80%) होता है। इसके बाद और सरेमिक एवं ग्लास में 7% होता है। लिथियम आधारित बैटरी का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और ग्रिड स्टोरेज में भी हो रहा है।

लिथियम का वैश्विक व्यापार

अप्रसंस्कृत लिथियम (एचएस 253090) से तात्पर्य लिथियम अयस्क और उसके कन्सेंट्रेशन से है। इसके व्यापार में ऑस्ट्रेलिया 49.2% की वैश्विक हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़ा निर्यातक रहा, जबकि वर्ष 2021 में चीन सबसे बड़ा आयातक रहा, जिसकी वैश्विक हिस्सेदारी 58.1% रही।

प्रसंस्कृत लिथियम के मामले में चिली वर्ष 2021 में 882.9 मिलियन यूएस डॉलर के कुल निर्यात के साथ लिथियम कार्बोनेट का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता रहा। लिथियम कार्बोनेट के वैश्विक निर्यात में इसकी हिस्सेदारी 72.8% की रही। 2021 में बोलीविया 0.8% की हिस्सेदारी के साथ 10वां बड़ा निर्यातक रहा। चीन (36.8%), दक्षिण कोरिया (25.2%) और जापान (13.6%) लिथियम कार्बोनेट के सबसे बड़े आयातक रहे। वर्ष 2021 में भारत लिथियम कार्बोनेट का 10वां सबसे बड़ा आयातक (8.8 मिलियन यूएस डॉलर) रहा, जिसकी हिस्सेदारी 0.6% रही। वर्ष 2021 में 763.9 मिलियन यूएस डॉलर के निर्यात के साथ चीन लिथियम ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड (HS-282520) का सबसे बड़ा निर्यातक रहा, जिसकी कुल निर्यात में 68.6% की वैश्विक हिस्सेदारी रही। इसके बाद कुल निर्यात में यूएस और चिली की हिस्सेदारी क्रमशः 8.8% और 8.6% रही, जबकि रूस की हिस्सेदारी 7.1% रही।

भारत की लिथियम आवश्यकताएं पूरी करने की रणनीतियां

भारत ने 2030 तक 500 GW की गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने और CO₂ उत्सर्जन को एक बिलियन टन तक कम करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। तथापि, वर्तमान में कच्चा माल और प्रौद्योगिकी भारत में लिथियम-आयन बैटरी के विनिर्माण में प्रमुख बाधाएं हैं।

वैश्विक संबद्धताएं: भारत को अपने बैटरी विनिर्माण, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ऊर्जा भंडारण और ऊर्जा परिवर्तन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए बड़े पैमाने पर लिथियम आपूर्ति की आवश्यकता है। भारत महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों के लिए संयुक्त अन्वेषण गतिविधियों में सहयोग के लिए अन्य देशों में अपने राजनयिक संबद्धताओं का सदुपयोग कर रहा है। खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड (केएबीआईएल), केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के तीन उद्यमों नामतः नैशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (नाल्को), हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल), और मिनरल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड को संयुक्त उद्यम के रूप प्रवर्तित किया जाता रहा है।

केएबीआईएल ने एक अध्ययन के जरिए 12 खनिजों- लिथियम, कोबाल्ट, जर्मनियम, इंडियम, बेरिलियम, नाइओबियम, सेलेनियम, गैलियम, टैंटलम, टंगस्टन, बिस्मथ और टिन को चिह्नित किया है, जिनमें यह अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना और व्यावसायिक साझेदारी बनाना चाहता है। इन 12 में से लिथियम और कोबाल्ट को प्रकृति में सबसे महत्वपूर्ण और रणनीतिक होने के रूप में चिह्नित किया गया है। इस अध्ययन और चयन मानदंड के आधार पर विदेशों में खनिज परिसंतियों के अधिग्रहण की संभावनाओं का पता लगाने के लिए चुनिंदा स्रोतों का चयन किया गया है। अभी तक चयनित ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली आदि जैसे स्रोत देशों के साथ बातचीत चल रही है, जो महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों, विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया में हार्ड रॉक संरचनाओं में लिथियम और कोबाल्ट से और लैटिन अमेरिकी देशों की तरह SALAR के विशाल विस्तार में ब्राइन के रूप में लिथियम से संपन्न हैं।

घरेलू अन्वेषण: वार्षिक फील्ड सीजन प्रोग्राम (एफएसपी) के तहत भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) ने आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार,

छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, जम्मू-कश्मीर, मध्य प्रदेश, मेघालय और राजस्थान में पिछले पांच वर्षों में 20 लिथियम परियोजनाएं शुरू की हैं। एफएसपी 2022-23 के तहत, जीएसआई ने छह राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 18 लिथियम परियोजनाएं शुरू की हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने पहली बार जम्मू-कश्मीर (यूटी) के रियासी जिले के सलाल-हाइमाना क्षेत्र में 5.9 मिलियन टन के लिथियम अनुमानित संसाधन (जी3) स्थापित किए हैं।

नीतिगत सिफारिशें

लिथियम त्रिकोण देशों के साथ भारत की संबद्धता हाल के वर्षों में उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है। भारत अपनी बढ़ती ऊर्जा जरूरतों की पूर्ति और स्वच्छ एवं अधिक संपोषी ऊर्जा प्रणाली की ओर बढ़ने के लिए प्रयासरत है। ऐसे में, लिथियम की निरंतर आपूर्ति हासिल करना एक रणनीतिक प्राथमिकता बन गई है।

व्यापार संबंधों में सुधार: भारत को अर्जेंटीना और बोलीविया के साथ द्विपक्षीय पीटीए के दायरे के साथ-साथ चिली के साथ संभावित एफटीए का भी मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। भारत को दक्षिण अमेरिका में अपने निर्यात के लिए शिपिंग लागत कम करने पर भी कार्य करने की जरूरत है।

भारतीय खनन क्षेत्र का विकास करना: देश में खनन संभावनाओं में सुधार के लिए अन्वेषण के जरिए संसाधन आधार और भंडार को बढ़ाना, विनियामकीय देरी को कम करना, बुनियादी ढांचागत, मानव पूंजी और तकनीकी क्षमताओं का विकास करना और एक मजबूत सूचना, शिक्षा और संचार रणनीति बनाना आवश्यक है।

बैटरी आपूर्ति शृंखलाओं में मूल्य कैप्चर करना: इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लिथियम आयन बैटरियों के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले अन्य मध्यवर्ती उत्पादों के साथ-साथ परिष्कृत लिथियम यौगिकों की आवश्यकता होगी। घरेलू लिथियम प्रसंस्करण और शोधन क्षमताओं का निर्माण वैश्विक बैटरी बाजारों में आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत की लागत प्रतिस्पर्धा में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण होगा।

संबंधों के समान आधार: अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली जैसे संसाधन संपन्न देशों से आयात करने के साथ-साथ लेन-देन संबंधों से आगे बढ़ना और साझा राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों जैसे आधार पर संबंध विकसित करना महत्वपूर्ण है। दोनों क्षेत्रों में अपनी ऊर्जा सुरक्षा में सुधार के लिए बहुत से साझा हित हैं।

अनुसंधान एवं विकास को बढ़ाना: अंतरराष्ट्रीय खनन रियायतों के अलावा, ग्रीन बंधन और आपूर्ति को अधिक लचीला बनाने के लिए खनिजों के उत्खनन, संकेंद्रण, पृथक्करण और शुद्धिकरण के तरीकों को इष्टतम बनाने के लिए अनुसंधान एवं विकास प्रयास बढ़ाने की जरूरत है। उच्चतर ऊर्जा घनत्व एवं चार्ज-डिस्चार्ज चक्रों की अधिक संख्या के साथ उन्नत बैटरी प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास में निवेश से भारत को अधिक संसाधन दक्षता हासिल करने में मदद मिलेगी। ■

भारत से मोटे अनाजों का उत्पादन और निर्यात बढ़ाना

– जाह्नवी सिंह, मुख्य प्रबंधक,
अशोक सिंह, अधिकारी

बालियों के रूप में छोटे-छोटे दाने वाली खास तरह की फसल को मिलेट्स या मोटा अनाज कहते हैं। ये गर्म मौसम की सालाना फसलें हैं। मूलतः एशिया और अफ्रीका में उगाई जाने वाली इन फसलों का उत्पादन अब दुनिया के अन्य क्षेत्रों में भी किया जाने लगा है। मानवीय आहार के अलावा मोटे अनाज का उपयोग पशुधन चारे के रूप में भी किया जाता है। क्योंकि ये पशुओं के लिए पोषक तत्वों के अहम स्रोत होते हैं। चूंकि मोटे अनाज में विभिन्न औषधीय गुण भी होते हैं, इसलिए इसका उपयोग भोजन और चारे के अलावा पारंपरिक चिकित्सा पद्धति में विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए हर्बल उपचार के रूप में भी किया जाता है।

ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाई जाने वाली मोटे अनाज की प्रमुख किस्में हैं। इनके अलावा, छोटे-मोटे अनाज जैसे प्रोसो (चीना), कोदो (कोदरा, अरिकेलु), कंगनी/कोर्रा, वरई, सावा, कुटकी, फोनियो और अन्य छोटे-मोटे अनाज की अन्य किस्में हैं, जिनकी खेती वैश्विक स्तर पर की जाती है।

वैश्विक परिदृश्य

मार्केटिंग वर्ष 2023¹ के दौरान, मोटे अनाज का वैश्विक उत्पादन 94.1 मिलियन मिट्रिक टन रहा², जिसमें मोटे अनाज की खेती के रकबे में वृद्धि के कारण 7.4% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की गई। मार्केटिंग वर्ष 2023 के दौरान 17.6 मिलियन मिट्रिक टन उत्पादन के साथ भारत मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक रहा, जिसकी वैश्विक उत्पादन में 18.7% की हिस्सेदारी रही। इस अवधि के दौरान, यूएसए 9.7 मिलियन मिट्रिक टन उत्पादन के साथ मोटे अनाज का दूसरा बड़ा उत्पादक रहा। मार्केटिंग वर्ष 2023 के दौरान, मोटे अनाज के अन्य प्रमुख उत्पादकों में नाइजीरिया (मोटे अनाज के वैश्विक उत्पादन में 9.2% की हिस्सेदारी), सूडान (7.0%), चीन (6.1%) और इथियोपिया (5.8%) शामिल रहे। मोटे अनाज में ज्वार एक महत्वपूर्ण श्रेणी है। मार्केटिंग वर्ष 2023 के दौरान, ज्वार का वैश्विक उत्पादन 62.3 मिलियन मीट्रिक टन रहा, जिसकी इस अवधि में मोटे अनाज के वैश्विक उत्पादन में 66.3% की हिस्सेदारी रही।

वर्ष 2021 के दौरान, मोटे अनाज का वैश्विक निर्यात 3.9 बिलियन यूएस डॉलर का रहा, जिसमें 67.5% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हुई। अगले वर्ष 2022 के दौरान 9.7% की वृद्धि से मोटे अनाज का निर्यात 4.3 बिलियन के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया। हाल के वर्षों में मोटे अनाज का वैश्विक निर्यात अच्छा रहा है। 2018 से 2022 के दौरान इसके निर्यात में 26.6% की सीएजीआर दर्ज की गई। वर्ष 2022 के दौरान, ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक यूएसए मोटे अनाज का सबसे बड़ा निर्यातक भी रहा। इस अवधि में मोटे अनाज के

वैश्विक निर्यात में आधे से भी अधिक की हिस्सेदारी यूएसए की रही। 2022 के दौरान, ऑस्ट्रेलिया 811.7 मिलियन यूएस डॉलर के निर्यात के साथ दूसरा बड़ा निर्यातक रहा, जिसकी मोटे अनाज के वैश्विक निर्यात में 19.0% की हिस्सेदारी रही। वर्ष 2022 में मोटे अनाज के अन्य प्रमुख निर्यातकों में अर्जेंटीना (मोटे अनाज के वैश्विक निर्यात में 8.6% की हिस्सेदारी), कनाडा (3.3%), फ्रांस (2.4%) रूस (2.4%) और भारत (1.6%) शामिल रहे।

भारत का मोटा अनाज परिदृश्य

वर्ष 2022-23 के दौरान, भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार, मोटे अनाज का उत्पादन 17.2 मिलियन टन दर्ज किया गया, जिसमें 7.2% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2013-14 से 2022-23 के दौरान भारत के मोटे अनाज के उत्पादन में वृद्धि (-) 0.04% की सीएजीआर के साथ कुछ धीमी रही।

वर्ष 2022-23 के दौरान, भारत से मोटे अनाज का निर्यात 75.5 मिलियन यूएस डॉलर का रहा, जिसमें 19.9% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की गई। भारत से मोटे अनाज के शीर्ष आयातक मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया क्षेत्र हैं। वर्ष 2022-23 के दौरान, भारत से मोटे अनाज का सबसे बड़ा आयातक यूई रहा, जिसे 13.3 मिलियन यूएस डॉलर का निर्यात किया गया और भारत से मोटे अनाज के निर्यात में इसका 17.7% हिस्सा रहा। 2022-23 के दौरान, भारत से मोटे अनाज के अन्य प्रमुख आयातकों में सऊदी अरब (भारत से मोटे अनाज के निर्यात का 13.8% हिस्सा), नेपाल (7.4%), बांग्लादेश (4.9%) और यूएसए (4.1%) शामिल रहे। भारत मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है; इसके बावजूद उत्पादन का 0.9% ही निर्यात किया गया। क्योंकि इसका अधिकांश उत्पादन घरेलू खपत में उपयोग कर लिया जाता है। इसके विपरीत, 2021 में यूएसए ने अपने मोटे अनाज के उत्पादन का 57.1%, ऑस्ट्रेलिया ने 95.7% और अर्जेंटीना ने 63.3% हिस्सा निर्यात किया।

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत के प्रस्ताव पर वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में घोषित किया। मोटे अनाज को बढ़ावा देने के प्रयास के तहत भारत सरकार ने भारतीय मोटे अनाज और मूल्य-वर्धित उत्पादों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 कार्यक्रम आयोजित किया। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार विभिन्न अंतरराष्ट्रीय व्यापार एक्सपो और क्रेता-विक्रेता बैठकों में निर्यातकों, किसानों और व्यापारियों की भागीदारी को सुगम बनाने की दिशा में काम कर रही है। विभिन्न राज्य सरकारें अपने राज्यों में मोटे अनाज की खेती और खपत को बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाएं लागू कर रही हैं। इनमें ओडिशा मिलेट मिशन, आंध्र प्रदेश मिलेट मिशन, तमिलनाडु मिलेट मिशन आदि जैसी योजनाएं शामिल हैं।

1 यूएसडीए विदेशी कृषि सेवाओं द्वारा माने गए विपणन वर्ष को संदर्भित करता है। कुछ अपवादों को छोड़कर, संदर्भ अवधि सितंबर से अगस्त है।

2 यूएसडीए डेटाबेस के अनुसार ज्वार और मोटा अनाज शामिल है।

मोटे अनाज का उत्पादन और निर्यात बढ़ाने के लिए रणनीतियां

मोटे अनाज का निर्यात बढ़ाने के लिए लक्षित बाजार: भारत का लक्ष्य विभिन्न मोटा अनाज श्रेणियों के लिए संभावित लक्षित बाजारों को चिह्नित कर मोटे अनाज के निर्यात को बढ़ाना है। 'भारत से मोटे अनाज का उत्पादन और निर्यात बढ़ाना' शीर्षक वाले एक्जिम बैंक के अध्ययन में इंडोनेशिया, नेपाल, यूएई, यूएसए, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, ओमान और श्रीलंका जैसे बाजारों को लक्ष्य करने की सिफारिश की गई है। अध्ययन में ज्वार के लिए चिह्नित किए गए संभावित बाजारों में चीन, सूडान, जिबूती, जिम्बाब्वे, स्पेन, इथियोपिया, इरिट्रिया, इटली, दक्षिण अफ्रीका और जापान शामिल हैं।

एक्जिम बैंक के इस अध्ययन में निर्यातों को अनुकूल बनाने के लिए बाजार विविधीकरण की आवश्यकता, विशेषकर उच्च बाजार संकेंद्रण वाली श्रेणियों में विविधीकरण पर जोर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, मोटे अनाज के शीर्ष आयात बाजारों में प्रवेश करने के लिए उन बाजारों में मौजूदगी बढ़ाने की रणनीति आवश्यक है।

मूल्य-वर्धित उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन: मोटे अनाज का आटा और अन्य मूल्य-वर्धित उत्पादों, जैसे स्नैक्स, रेडी टु कुक/रेडी टु ईट उत्पादों, किण्वित (फर्मेंटेड) मिलेट आटा, उबले हुए मोटे अनाज की तैयार वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने की काफी संभावना है। पौष्टिकता और ग्लूटेन-मुक्त विशेषताओं से प्रसंस्कृत मोटे अनाज की बड़े पैमाने पर बढ़ती अंतरराष्ट्रीय मांगों को देखते हुए मिलेट माल्ट और पंछियों के दाने जैसी वस्तुओं के निर्यात के अपार अवसर हो सकते हैं।

जैविक मोटे अनाज के निर्यात को बढ़ाना: एक्जिम बैंक के अध्ययन में वैश्विक स्तर पर जैविक मोटे अनाज उत्पादों की बढ़ती मांग पर भी प्रकाश डाला गया है। भारत एपीडा जैसे सरकारी निकायों से संस्थागत सहयोग का लाभ उठाते हुए निर्यात बाजार में मौजूदगी बढ़ा सकता है। जागरूकता कार्यक्रमों और मार्केटिंग अभियानों सहित उद्यमशीलता और मिलकर की जाने वाली पहलों जैसे प्रयास जैविक मोटा अनाज उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे।

गैर-टैरिफ बाधाओं का समाधान: मोटे अनाज के निर्यातों पर भारत के सामने भले ही अपेक्षाकृत रूप से न्यून टैरिफ हों, किन्तु नॉन-टैरिफ उपायों (एनटीएम) के मामले में उल्लेखनीय चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। एक्जिम बैंक के अध्ययन में एनटीएम समाधानों के लिए गुणवत्ता परीक्षण और निरीक्षण अवसंरचना को सुदृढ़ करने की सिफारिश की गई है। इस अध्ययन में मोटे अनाज के प्रमुख उत्पादक राज्यों में प्रयोगशालाओं की स्थापना और उनमें उपकरणों सहित तकनीकी बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए एक व्यापक कार्यक्रम सुझाया गया है। मोटे अनाज के निर्यातकों के लिए एक मैनुअल भी प्रकाशित किया जा सकता है, जिसमें निर्यात प्रोटोकॉल, गुणवत्ता दिशानिर्देश और प्रमाणन आवश्यकताएं बताई जाएं तथा जटिल विनियमों और मानकों को समझने में निर्यातकों की सहायता की जाए।

सुविचारित नीतिगत निर्णयों के लिए डेटा मुद्दों का समाधान: सुविचारित नीतिगत निर्णयों के सुगमीकरण के लिए, एक्जिम बैंक के अध्ययन में प्रसंस्कृत मोटे अनाज उत्पादों के लिए विशिष्ट एचएस-कोड की अनुपस्थिति के विषय में प्रकाश डाला गया है। इसमें प्रसंस्कृत मोटे अनाज के लिए अलग एचएस कोड बनाने तथा भारत में प्रसंस्कृत मोटे अनाज के उत्पादों के लिए आठ अंकों का वर्गीकरण शुरू करने के लिए विश्वा सीमा शुल्क संगठन से अनुरोध करने की सिफारिश भी की गई है।

भारत में मोटे अनाज की मूल्य शृंखला को सुदृढ़ करना: भारत को गुणवत्ता वाले मोटे अनाज और उसके उत्पादों के स्थिर स्रोत के रूप में स्थापित करने के लिए मोटे अनाज की मूल्य शृंखला को बढ़ाने के प्रयासों में मूल्य शृंखला में विशिष्ट चुनौतियों का समाधान करना शामिल है। एक्जिम बैंक के अध्ययन में निम्नलिखित प्रमुख रणनीतियों पर जोर दिया गया है:

छोटे मोटे अनाज के लिए बीज केंद्र क्षमता बढ़ाना: बीज आपूर्ति शृंखला को सुदृढ़ करने, मोटे अनाज की नई किस्मों के व्यवसायीकरण को सुगम बनाने तथा छोटे-मोटे अनाज के लिए बीज प्रतिस्थापन दर में सुधार लाने के लिए बीज केंद्र प्रस्तावित किए गए हैं। साथ ही, स्थान विशेष की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली किस्मों को विकसित करने और हाइब्रिड बीजों के उपयोग को बढ़ावा देने की भी आवश्यकता है।

बायो-फोर्टिफाइड मोटे अनाज के बीज के उपयोग को प्रोत्साहन: मोटे अनाज का जैव-सुदृढ़ीकरण आनुवंशिक परिचालन के जरिए पौष्टिक रूप से समृद्ध मोटे अनाज की किस्मों के विकास से जुड़ा है। अध्ययन में पोषण सुरक्षा संबंधी चिंताओं वाले क्षेत्रों में जैव-फोर्टिफाइड मोटे अनाज की खेती और निर्यात बढ़ाने को प्रोत्साहित किया गया है।

मोटे अनाज की क्लस्टर कृषि को प्रोत्साहन: क्लस्टर कृषि से मोटे अनाज की खेती में उत्पादकता और दक्षता बढ़ सकती है, और बदले में निर्यात योग्य सरप्लस फसल मिल सकती है। ओडिशा जैसे सफल क्लस्टर आधारित मॉडलों को बढ़ावा जिसका अनुकरण किया जा सकता है।

कार्बन बाजारों के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाना: मोटे अनाज की खेती की कम कार्बन तीव्रता को देखते हुए, कार्बन ट्रेडिंग और ऑफसेटिंग पहलों में हिस्सा लेने से मोटे अनाज के किसानों और निर्यातकों के लिए संभावित आय के स्रोतों का पता लगाने में मदद मिलेगी। साथ ही, भारत की पर्यावरणीय स्थिरता को भी बढ़ावा मिलेगा। भारत सरकार कृषि में कार्बन ट्रेडिंग से संबंधित विनियमों के लिए कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम के अंतर्गत एक धारा शामिल करने पर विचार कर सकती है।

लागत मुद्दों का समाधान: उत्पादन के बाद की प्रक्रिया में सुधार, क्लस्टर कृषि को प्रोत्साहन और किसान उत्पादक संगठनों को मजबूत कर लागत संबंधी मुद्दों का समाधान करने की आवश्यकता है। छोटे मोटे अनाजों के लिए एमएसपी लागू करने और निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों में छूट योजना के तहत मोटे अनाज के निर्यात की दरें बढ़ाने जैसे विकल्पों से मूल्य प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है।

मोटे अनाजों की खपत बढ़ाने के लिए मार्केटिंग रणनीति: मोटे अनाज आधारित व्यंजनों को लोकप्रिय बनाकर और मोटे अनाज वाले उत्पादों के लिए भौगोलिक उपदर्शन (जीआई) टैग का लाभ उठाते हुए मार्केटिंग प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण होगा।

मोटे अनाज आधारित व्यंजनों की खपत को लोकप्रिय बनाना: भारत सरकार घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिलेट आधारित व्यंजनों को लोकप्रिय बनाने के लिए खाद्य संवर्धन अभियान शुरू कर सकती है।

भौगोलिक संकेतक (जीआई) टैग: अधिक स्थानीय दुर्लभ मोटे अनाज की किस्मों के साथ-साथ मोटे अनाज के ऐसे उत्पादों को चिह्नित करने संबंधी पहल की आवश्यकता है, जिन्हें जीआई दर्जा दिया जा सके। इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र तैयार करने की आवश्यकता है कि जीआई ब्रांड के तहत मार्केटिंग किए जाने वाले सभी मिलेट उत्पाद न्यूनतम निर्दिष्ट मानकों को पूरा करने वाले हों। ■

भारत में इस्पात उद्योग

- राहुल मजूमदार, उप महाप्रबंधक
साक्षी गर्ग, उप प्रबंधक

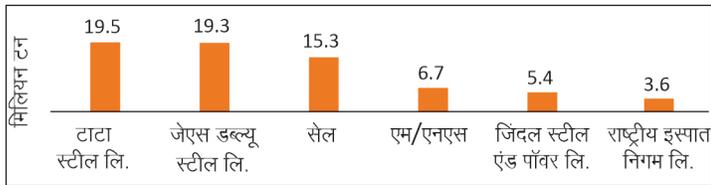
इस्पात (स्टील) एक मानव निर्मित मिश्र धातु है जो लोहे, कार्बन, सिलिकॉन और मँगनीज को एक साथ मिलाकर बनाया जाता है और शुद्ध लोहे की तुलना में कठोर और मजबूत होता है। इस्पात दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग और निर्माण सामग्री है, जिसे संपत्ति के नुकसान के बिना रिसाइकल किया जा सकता है। भारतीय इस्पात क्षेत्र में वृद्धि लौह अयस्क जैसे कच्चे माल की घरेलू उपलब्धता और किफायती श्रम के कारण है। राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 के अनुसार, कच्चे इस्पात की उत्पादन क्षमता 2030-31 तक 300 मिलियन टन तक पहुंचने की उम्मीद है।

उत्पादन

कच्चा इस्पात: वर्ष 2022 में, वैश्विक कच्चे इस्पात का उत्पादन 1878.5 मिलियन टन (एमटी) पहुंच गया, जिसमें 2021 के 1960.4 मिलियन टन से (-) 4.2% की गिरावट आई। चीन कच्चे इस्पात के उत्पादन में अग्रणी है, जिसने 2022 में 1034.7 मिलियन टन का उत्पादन किया, हालांकि 2021 की तुलना में उत्पादन में (-) 2.1% की गिरावट आई। वैश्विक स्तर पर भारत कच्चे इस्पात का दूसरा बड़ा उत्पादक है, जिसका उत्पादन 2022 में 5.5% की वार्षिक वृद्धि के साथ 124.7 मिलियन टन रहा। 2022 में कच्चे इस्पात के अन्य प्रमुख उत्पादकों में जापान (89.2 एमटी), यूएसए (80.7 एमटी), रूस (71.5 एमटी) और दक्षिण कोरिया (65.9 एमटी) शामिल रहे।

तैयार इस्पात: वर्ष 2022-23 में, भारत में तैयार इस्पात का उत्पादन 122.3 एमटी रहा, जिसमें पिछले साल के 113.6 एमटी की तुलना में 7.6% की वृद्धि दर्ज की गई।

2022-23 में भारत में तैयार इस्पात का उत्पादन



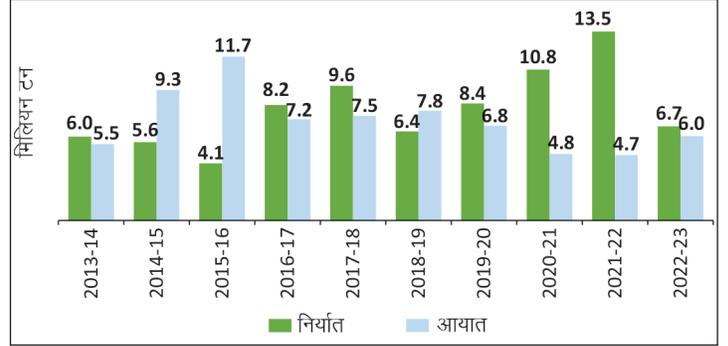
स्रोत: सीआईईई इंडस्ट्री आउटलुक

दूसरी ओर, 2022-23 में खपत 119.9 एमटी कम रही। निराशाजनक वैश्विक परिवेश के बावजूद, घरेलू इस्पात मांग पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 13% की वृद्धि के साथ अच्छी बनी रही। यह वृद्धि अवसंरचना को बढ़ावा देने, मजबूत आवास परियोजनाओं तथा ऑटो क्षेत्र से बढ़ती मांग के कारण रही। क्रिसिल के अनुमानों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान संबद्ध क्षेत्रों से अच्छी मांग और सरकार के कैपेक्स बढ़ाने से घरेलू मांग में 6.8% की वृद्धि होने की उम्मीद है।

अंतरराष्ट्रीय व्यापार

भारत तैयार इस्पात के निवल निर्यातक के रूप में उभरा है। 2022-23 में कुल 122.3 एमटी तैयार इस्पात के उत्पादन में से 6.7 एमटी का निर्यात हुआ। वर्ष के दौरान 6 एमटी के बराबर आयात रहा। मूल्य के संदर्भ में, 2022-23 में 9.5 बिलियन यूएस डॉलर के आयात के मुकाबले 10.1 बिलियन यूएस डॉलर के तैयार इस्पात का निर्यात रहा। 2022-23 में भारत के शीर्ष निर्यात भागीदारों में इटली (11.8%), यूएसए (10.1%), बेल्जियम (8%), यूई (8%) और वियतनाम (5.5%) शामिल रहे। शीर्ष निर्यातकों में दक्षिण कोरिया (26.5%), चीन (25.3%), जापान (14.9%), इंडोनेशिया (4.7%) और वियतनाम (4.2%) शामिल रहे।

तैयार इस्पात में भारत का वैश्विक व्यापार



स्रोत: सीआईईई इंडस्ट्री आउटलुक

निर्यात पर कार्बन सीमा समायोजन कर तंत्र (सीबीएएम) का प्रभाव: क्रिसिल के अनुसार, सीबीएएम के पूर्ण कार्यान्वयन के बाद यूरोपीय संघ को भारत के इस्पात निर्यात की लागत 17% तक बढ़ सकती है, जो उत्सर्जन के प्रभाव को कम करने के लिए आवश्यक प्रकटीकरण और कार्बन क्रेडिट की खरीद को अनिवार्य बनाता है। सीबीएएम के तहत निर्यातकों को 01 अक्टूबर, 2023 से उत्सर्जन की तिमाही रिपोर्ट बनाना और 31 दिसंबर, 2025 से उनके ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के लिए उत्सर्जन व्यापार प्रणाली (ईटीएस) प्रमाणपत्र खरीदना आवश्यक होगा। कार्बन-न्यूट्रल तकनीक की अनुपस्थिति में, उद्योगों को 2025 में 100% से शुरू होकर 2034 तक 0% पर समाप्त होने वाला मुफ्त भत्ता आवंटित किया गया है। ईटीएस कर धीरे-धीरे उस हिस्से पर लागू होगा जिसे यह भत्ता नहीं मिलता है। कई अन्य देश यूरोपीय संघ की तर्ज पर उत्सर्जन आधारित टैरिफ बाधाएं लगाने के विभिन्न चरणों में हैं। इनमें यूएसए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं।

इस्पात उत्पादन में न्यून कार्बन उत्सर्जन वाली नई प्रौद्योगिकियां

कोकिंग कोल का उपयोग मुख्य रूप से लोहा बनाने की प्रक्रिया के दौरान ब्लास्ट फर्नेस में उत्सर्जन कम करने वाले एजेंट के रूप में किया जाता है। तथापि, कोकिंग-कोल के उपयोग से प्रति टन कच्चे इस्पात के निर्माण में कार्बन उत्सर्जन अधिक होता है, क्योंकि कोक कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है। पारंपरिक ब्लास्ट फर्नेस - बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस (बीएफ-बीओएफ) में, कार्बन उत्सर्जन आमतौर पर उच्चतम (लगभग 2.4 टन/टन कच्चा इस्पात) होता है। भारत बीएफ-बीओएफ रूट के माध्यम से कच्चे इस्पात का लगभग 45% उत्पादन करता है। इस्पात मंत्रालय 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए विद्युत मंत्रालय, नवीन और अक्षय ऊर्जा मंत्रालय, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नीति आयोग आदि जैसे संबंधित हितधारकों के साथ लगातार जुड़ रहा है।

लौह और इस्पात मदों के लिए निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (आरओडीटीईपी) योजना के तहत निर्यात लाभों को बढ़ावा देने हेतु विशेष इस्पात के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना और राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन जैसी नीतियाँ भारत में इस्पात उत्पादन को बढ़ावा दे रही हैं और हरित इस्पात निर्माण को सुगम बना रही हैं। विश्व इस्पात संघ के अनुसार, इस्पात की वैश्विक मांग क्रमशः 2.3% और 1.7% की तुलना में देश में वर्ष 2023 और 2024 में क्रमशः 7.3% और 6.2% की अच्छी वृद्धि रहने का अनुमान है। ■

स्थानीय श्रम बाजार पर अप्रवासियों और उनके प्रभाव पर निबंध

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (इंडिया एक्विजिमेंट बैंक) ने 1989 में अंतरराष्ट्रीय आर्थिक शोध वार्षिक (ईरा) सम्मान की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य भारत और विदेशों में विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थाओं में भारतीय नागरिकों द्वारा अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र, व्यापार, विकास और संबंधित वित्तपोषण में शोध को बढ़ावा देना है। 'स्थानीय श्रम बाजार पर अप्रवासियों और उनके प्रभाव पर निबंध' शीर्षक वाला यह अध्ययन डॉ. रोनिन मुखर्जी की 2022 में ईरा सम्मान से पुरस्कृत थीसिस पर आधारित है। डॉ. मुखर्जी ने 2022 में ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय, वैंकूवर, कनाडा से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी।

अप्रवासियों के प्रवेश का श्रम बाजार पर प्रभाव गहन चर्चा और विश्लेषण का विषय रहा है। विशेष रूप से समग्र कल्याणकारी प्रभावों को समझने के लिए अलग-अलग कौशल वाले देसी श्रमिकों पर प्रभाव का विशेष महत्व है। अध्ययन के प्रथम अध्याय में विशेष रूप से 1970 और 2000 के बीच अमेरिकी श्रम बाजार का विस्तृत अनुभवजन्य विश्लेषण है, जिसका उद्देश्य बढ़े हुए अप्रवास और एकीकरण दरों में गिरावट के बीच संबंध स्थापित करना है। इस अध्याय में स्थानीय श्रम बाजार पर अप्रवासियों की दस्तक के संभावित प्रभावों पर चर्चा की गई है तथा इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि किस प्रकार यह कौशल मिक्स को बदलता है तथा स्थानीय और अप्रवासी श्रमिकों के बीच वेतन के अंतर को प्रभावित करता है।

प्रस्तावित अनुभवजन्य रणनीति विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों, उद्योगों और व्यवसायों में अप्रवासी दस्तक और संघ सदस्यता के बीच सहसंबंध की पड़ताल की गई है। अध्ययन में अप्रवासी दस्तक और एकीकरण दरों के बीच लगातार नकारात्मक सहसंबंधों के अवलोकन के लिए अंतरराष्ट्रीय संदर्भों का भी उपयोग किया गया है। कार्य-कारण प्रमाणित करने के लिए, अध्ययन में एथनिक एन्क्लेव पद्धति पर आधारित एक इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल (IV) दृष्टिकोण नियोजित कर इंडोजेनेटि चिंताओं और संभावित अप्रत्यक्ष प्रभावों की पड़ताल की गई है। चौथे अनुमान के अनुसार 1980 और 2000 के बीच एकीकरण दरों में गिरावट का महत्वपूर्ण हिस्सा (लगभग 48%) कम कुशल अप्रवासियों के आने के चलते रहा हो सकता है। सुदृढ़ता जांच में काम के अधिकार कानूनों, उद्योग क्षेत्रगत बदलावों जैसे स्पष्टीकरणों और तकनीकी परिवर्तनों को यूनियन डेन्सिटी में गिरावट के एकमात्र कारण के रूप में को खारिज किया गया है। यह संघ दरों पर कम कौशल वाले अप्रवासियों में वृद्धि के पर्याप्त प्रभाव की पुष्टि करती है।

इसके अलावा, इस अध्ययन में खोज-सैद्धांतिक अवसंरचना पर आधारित एक सैद्धांतिक मॉडल निरूपित किया गया है, जो अप्रवासी प्रवेश और एकीकरण में गिरावट के बीच कारण तंत्र को औपचारिक रूप से प्रदर्शित करता है। यह मॉडल स्पष्ट करता है कि कैसे अप्रवासी प्रवाह विभिन्न कौशल स्तरों पर एकीकरण को प्रभावित करता है, जिससे कौशल वितरण में एकीकरण की सघनता होती है। अप्रवासियों के प्रवेश के बाद कौशल

की पूरकता के कारण उच्च कुशल मूल-निवासी श्रमिक अधिक वेतन पाने के लिए संघ से बाहर निकल जाते हैं। जबकि कम कुशल श्रमिक फर्म के लिए उतने उपयोगी नहीं होने के चलते संघ को छोड़ देते हैं। सभी कौशल डेसील में संघीकरण यूनियनकरण दरों में उल्टे 'यू' आकार के संबंध और विभिन्न कौशल वाले मूल निवासी श्रमिकों के वेतन अंतर में परिवर्तन सहित इस मॉडल के पूर्वानुमान, अनुभवजन्य निष्कर्षों के अनुरूप हैं। अंततः इस कैलिब्रेटेड मॉडल का पूर्वानुमान है कि कम कौशल के अप्रवासी श्रमिकों के प्रवेश में वृद्धि एकीकरण दरों में दर्ज गिरावट के एक उल्लेखनीय अनुपात (लगभग 48-55%) को स्पष्ट कर सकती है।

यह पूर्वानुमान 1980 से 2000 के बीच की अवधि और 2000 से 2017 तक की बाद अवधि दोनों पर लागू किए जाने पर एक समान रहता है। कुल मिलाकर, यह विश्लेषण कम कुशल अप्रवासी प्रवेश में वृद्धि और यूएस में एकीकरण में कमी के बीच मजबूत कार्य-कारण संबंधों को दर्शाता है जो अनुभवजन्य सहसंबंध, इन्स्ट्रूमेंटल वेरिएबल अनुमान और सैद्धांतिक मॉडलिंग के जरिए प्रमाणित है। श्रमिक श्रमिक

स्थानीय श्रम बाजार पर अप्रवासियों के प्रभाव को समझने के लिए यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि पहली बार में उनका व्यवहार किससे प्रेरित होता है। अध्ययन के दूसरे अध्याय में बताया गया है कि विनिमय दर में उतार-चढ़ाव से कनाडा में अप्रवासियों के श्रम बाजार व्यवहार और आमदनी किस प्रकार प्रभावित होती है। अध्ययन में कनाडाई डॉलर के मूल्य में परिवर्तनों से अप्रवासी श्रमिकों की श्रम आय पर प्रभाव को समझने के लिए सर्वे ऑफ लेबर इन्कम एंड डायनेमिक्स (एसएलआईडी) और लान्जिटूडनल इमिग्रेशन डेटाबेस (आईएमडीबी) के डेटा का उपयोग किया गया है। अध्ययन में पाया गया है कि कनाडाई डॉलर के 10% बढ़ने से औसत अप्रवासी श्रमिक की श्रम आय में 0.36% की कमी आती है। आय में यह कमी मुख्य रूप से काम के घंटों में कमी के कारण होती है, जिससे एक सामान्य सप्ताह में घंटों की संख्या और काम किए गए कुल सप्ताह दोनों प्रभावित होते हैं।

अप्रवासी अपने श्रम आपूर्ति के समायोजन के द्वारा विनिमय दर में बदलावों के प्रति प्रतिकार करते हैं, आय में अधिकांश कमी काम के घंटों में कमी के

कारण आती है। इसके अतिरिक्त, कनाडाई डॉलर की तुलनात्मक वृद्धि की प्रतिक्रिया में अप्रवासियों के अंशकालिक कार्य करने की संभावना बढ़ जाती है। अध्ययन में अप्रवासी उप समूह द्वारा विविध प्रभाव भी पाया गया है, जहां नए प्रवासी विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं और कनाडा में अप्रवासियों के अधिक समय बिताने से यह प्रभाव कम हो जाता है, जो दर्शाता है कि अपने गृह देशों के साथ मजबूत संबंध रखने वाले लोग अधिक प्रभावित होते हैं। जातीय बस्तियों में बसे अप्रवासी तथा वे लोग जिनके पारिवारिक सदस्य अपने मूल देशों में रहते हैं, विनिमय दर के झटकों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं।

धन प्रेषणों (रेमिटेंस) संबंधी डेटा के विश्लेषण से पता चलता है कि विनिमय दर में उतार-चढ़ाव से धन भेजने वालों पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन भेजी गई कुल राशि अपरिवर्तित रहती है, जिससे पता चलता है कि अप्रवासी विदेशी मुद्रा में धन प्रेषण की एक स्थिर राशि बनाए रखते हैं। विकसित देशों से विकासशील देशों में आर्थिक बहिर्गमन के एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में धनप्रेषण के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। विशेष रूप से, अप्रवासियों का आर्थिक हित और धन प्रेषण के माध्यम से उनके अपने देश से संबंध, मेजबान देश, विशेष रूप से कनाडा में उनके श्रम बाजार के परिणामों पर उनके अपने देश की व्यापक आर्थिक स्थितियों के प्रभाव को समझने के महत्व को रेखांकित करते हैं। इस अध्ययन की प्रासंगिकता अप्रवासियों के प्रवेश और प्रवास की अवधि से संबंधित नीतिगत निहितार्थों तक है, विशेष रूप से कनाडाई अप्रवासी नीति के संदर्भ में, जो उच्च कुशल श्रम और उत्पादकता पर जोर देती है, लेकिन अप्रवासियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि और उनके अपने देशों के साथ संबंधों के आधार पर भिन्न हो सकती है।

लक्षित अर्थव्यवस्था की स्थितियों और यह अप्रवासी व्यवहार को कैसे प्रभावित कर सकती है, इस पर शोध एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए, अध्ययन के तीसरे अध्याय में अप्रवासियों से संबंधित आर्थिक साहित्य के दो पहलुओं के प्रतिच्छेदन पर विचार किया गया है: विकसित अर्थव्यवस्थाओं में अप्रवासियों का आर्थिक समावेश, विशेष रूप से मूल निवासी लोगों की तुलना में उनकी श्रम बाजार आय पर फोकस करना, और प्रवेश पर मैक्रोइकॉनॉमिक स्थितियां समय के साथ आय को कैसे प्रभावित करती हैं। इस अध्ययन का उद्देश्य अप्रवासियों के लिए मौजूदा आय पर प्रवेश के समय प्रारंभिक श्रम बाजार स्थितियों की प्रभाव की जांच कर शोध के इन दो क्षेत्रों को जोड़ना है। अध्ययन में पता लगाया गया है कि प्रवेश बिन्दु पर मंदी या आर्थिक स्थिति अप्रवासियों के दीर्घकालिक श्रम बाजार के परिणामों और आर्थिक एकीकरण को कैसे प्रभावित करती है।

मौजूदा साहित्य मुख्य रूप से कॉलेज स्नातकों पर आर्थिक मंदी के प्रभाव पर केंद्रित है, जो दर्शाता है कि आर्थिक संकट के दौरान बढ़ी हुई बेरोजगारी दरों के कारण दीर्घकालिक आय में कमी आ सकती है। हालांकि, इस

अध्ययन का उद्देश्य अप्रवासियों, श्रम बाजार में कम सुविधा प्राप्त एक समूह, पर प्रभावों की जांच करना है और यह विश्लेषण विभिन्न कौशल स्तरों और शैक्षणिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को शामिल करने के लिए किया गया है। यह शोध एक लान्जिटूडनल डेटासेट पर आधारित है, जो अप्रवासियों के कर रिटर्न को प्रवेश के समय उनकी प्रारंभिक स्थितियों से मिलाता है, जिससे अप्रवासियों की आय, मेजबान देश में समावेशन और प्रवासन निर्णयों पर प्रारंभिक श्रम बाजार स्थितियों के दीर्घकालिक प्रभावों के बारे में जानकारी मिलती है। यह अध्ययन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे यह समझ बनती है कि प्रवेश के समय आर्थिक परिस्थितियां अप्रवासी परिणामों को किस प्रकार प्रभावित कर सकती हैं।

इस अध्ययन में श्रम बाजार के पहले 15 वर्षों में अप्रवासियों की आय पर प्रारंभिक बेरोजगारी दर के प्रभाव का विश्लेषण किया गया है। प्राथमिक परिणाम बताते हैं कि बेरोजगारी में 3% की वृद्धि से आय में 7% की कमी आती है। यह प्रभाव केवल श्रम बाजार में बिताए गए समय के साथ कम होता है। प्रवेश के 10 साल बाद भी इसका प्रभाव महत्वपूर्ण बना रहता है। अध्ययन में श्रम बाजार में प्रवेश के समय बेरोजगारी दर और देश से बाहर नहीं बसने वाले अप्रवासियों की आय के आधार पर प्रवासन निर्णयों की पड़ताल की गई है। परिणाम बताते हैं कि बाहर निकलने वालों से कनाडा में रहने वाले अप्रवासी बेहतर प्रदर्शन करते हैं। यह सुधार तेजी से होता है, क्योंकि आठवें वर्ष के बाद आरंभिक बेरोजगारी दर से आय पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। अध्ययन में प्रवासन के निर्णय और कनाडा छोड़ने का विकल्प चुनने वाले अप्रवासियों की हिस्सेदारी की जांच की गई है।

इसमें पाया गया है कि अप्रवासियों का एक महत्वपूर्ण भाग पहले वर्ष में पलायन कर जाता है, तथा दूसरे और तीसरे वर्ष में यह संख्या बढ़ जाती है। बेरोजगारी में 3 अंकों की वृद्धि से तीसरे वर्ष में 4% अप्रवासी पलायन कर जाते हैं, तथा पांचवें वर्ष तक घटकर 1.5% रह जाता है। परिणाम बताते हैं कि कनाडा छोड़ने वाले अप्रवासियों का प्रदर्शन यहां रहने वालों की तुलना में बदतर होता है। अध्ययन में यह भी पाया गया है कि कनाडा में विकसित देशों के अप्रवासी लंबी अवधि में विकासशील अर्थव्यवस्था से आए लोगों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। पहले, विकसित देशों के अप्रवासी विकासशील अर्थव्यवस्था के अप्रवासियों के समान ही आय में कटौती का सामना करते हैं, लेकिन विकसित अर्थव्यवस्था से आए अप्रवासियों पर प्रभाव अधिक तेजी से खत्म होता है। यह प्रभाव 10 वर्ष के बाद भी महत्वपूर्ण बना रहता है।

निष्कर्ष: यह अध्ययन अप्रवासी प्रवेश के श्रम बाजार पर प्रभाव को समझने में योगदान देता है तथा यह भी बताता है कि किस प्रकार स्वदेश और विदेश दोनों स्थितियों के आधार पर अप्रवासी व्यवहार में भिन्नता आती है, तथा यह बहुमूल्य मूल्यवान नीतिगत विवरण प्रदान करता है। ■

इंडिया एक्जिम बैंक की ऋण-व्यवस्थाएं

सौजन्य : ऋण व्यवस्था समूह

भारत सरकार ने 2003-04 में भारत विकास पहल (आईडीआई) तैयार की, जिसे अब भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना (आईडीईएस) के रूप में जाना जाता है - जिसका मकसद, साझेदार देशों में आर्थिक और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्तपोषित करके भारत के विकास अनुभव को साझा करना; साझेदार देशों में सामाजिक-आर्थिक विकास करने की दिशा में, विकासशील साझेदार देशों को भारतीय निर्यात-आयात बैंक के माध्यम से रियायती ऋण-व्यवस्था (एलओसी) प्रदान करके क्षमता विकास और कौशल हस्तांतरण को सहयोग करना और वस्तुओं और सेवाओं में द्विपक्षीय व्यापार का संवर्धन करना है। नवीनतम आइडियाज़ दिशानिर्देश संशोधित किए गए हैं और 31 मार्च, 2022 से प्रभावी हैं।

संशोधित आइडियाज़ दिशानिर्देशों के तहत, रियायती वित्तपोषण योजना (सीएफएस) को आइडियाज़ योजना के एक भाग के रूप में आइडियाज़ 2022 में मिला दिया गया है। इसलिए इसमें आईडीईएस 2022 के तहत रियायती वित्तपोषण शामिल होगा, ताकि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण विदेशी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए बोली लगाने वाली भारतीय इकाइयों को सहयोग किया जा सके।

इंडिया एक्जिम बैंक विदेशी वित्तीय संस्थानों, क्षेत्रीय विकास बैंकों, संप्रभु सरकारों और विदेशों की अन्य संस्थाओं को ऋण-सहायता (एलओसी) प्रदान करता है। ताकि उन देशों के खरीदार भारत से विकासात्मक और अवसंरचनात्मक परियोजनाओं, उपकरणों, वस्तुओं और सेवाओं का आयात कर सकें।

भारत सरकार के सहयोग से प्रदान की गई ऋण-व्यवस्था के अंतर्गत, इंडिया एक्जिम बैंक भारतीय निर्यातकों को एफओबी/सीएफआर/सीआईएफ/सीआईपी आधार पर अनुबंध मूल्य की 100% प्रतिपूर्ति करता है। इन ऋणों के तहत कवर किए गए अनुबंधों के मूल्य की कम से कम 75% वस्तुएं और सेवाएं (पारामर्श सेवाओं सहित) भारत से ली जानी चाहिए। ऋण-व्यवस्थाओं ने भारत को उभरते बाजारों में परियोजना निष्पादन क्षमताओं का प्रदर्शन करने में सक्षम बनाया है। ऋण-व्यवस्थाओं ने हाल के वर्षों में, विशेष रूप से अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, ओशिनिया और सीआईएस के विकासशील देशों में

काफी गति हासिल करने में मदद की है। ऋण-व्यवस्थाओं ने भारत के राजनीतिक, रणनीतिक और वाणिज्यिक हितों को बढ़ावा देने के अलावा लाभार्थी देशों में भारत के लिए अपेक्षित राजनीतिक सद्भाव बनाने में मदद की है। ऋण-व्यवस्था भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत के साथ-साथ प्राप्तकर्ता विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे के विकास और क्षमता निर्माण में योगदान करने की इच्छा को प्रदर्शित करने में मदद करती है। ऋण व्यवस्थाएं प्राप्तकर्ता देश के बाजारों में आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात में भी मदद करती है, जिसमें भारत की उपस्थिति नहीं है। भारतीय निर्यातकों को शिपिंग दस्तावेजों के निगोशिएशन / सेवाओं के प्रावधान (अनुमोदित भुगतान शर्तों के अनुसार) के एवज में पात्र मूल्य का भुगतान मिल सकता है और वे खरीदार या खरीदार देश के जोखिम से चिंतामुक्त रह सकते हैं।

ऋण-व्यवस्थाएं संप्रभु सरकारों या उनके नामित एजेंसियों को प्रदान की जाती हैं। ताकि उन देशों में क्रेता वस्तुएं एवं सेवाओं का आस्थिगत भुगतान शर्तों पर भारत से आयात कर सकें। बैंक के पास 31 दिसंबर, 2023 तक 291 लाइन्स ऑफ क्रेडिट हैं, जो अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, ओशिनिया और सीआईएस में 68 से अधिक देशों को कवर करती है। इसमें 28.17 बिलियन यूएस डॉलर से अधिक की ऋण प्रतिबद्धताएं हैं, जो भारत के निर्यात के वित्तपोषण के लिए उपलब्ध हैं। इस प्रकार ऋण-व्यवस्थाएं भारत की परियोजनाओं, वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सुविधा प्रदान करने के लिए प्रभावी माध्यम है।

विस्तृत जानकारी के लिए कृपया संपर्क कीजिए :

श्री दीपक कुजूर,

सहायक महाप्रबंधक,

भारतीय निर्यात-आयात बैंक,

ऑफिस ब्लॉक, टॉवर 1, 7वीं मंजिल,

रिंग रोड के नजदीक, किदवई नगर (पूर्व)

नई दिल्ली-110023,

फोन: (011) 24607700

ईमेल: eximloc@eximbankindia.in ■

तिमाही गतिविधियां

सौजन्य : कॉर्पोरेट संचार समूह

लंदन स्टॉक एक्सचेंज के सस्टेनेबल बॉन्ड मार्केट (एसबीएम) प्लैटफॉर्म पर लिस्ट हुआ इंडिया एक्जिम बैंक का 1 बिलियन यूएस डॉलर का पहला 10 वर्षीय सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड



डॉ. विवेक जोशी, सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लंदन स्टॉक एक्सचेंज में मार्केट खोला गया। इस दौरान भारतीय निर्यात-आयात बैंक (इंडिया एक्जिम बैंक) की प्रबंध निदेशक सुश्री हर्षा बंगारी भी उपस्थित रहीं। यह मौका था, इंडिया एक्जिम बैंक के 1 बिलियन यूएस डॉलर के पहले 10 वर्षीय सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड के लंदन स्टॉक एक्सचेंज के सस्टेनेबल बॉन्ड मार्केट (एसबीएम) प्लैटफॉर्म पर लिस्टिंग का।

इंडिया एक्जिम बैंक ने यह बॉन्ड जनवरी 2023 में जारी किया था। इसी के साथ इंडिया एक्जिम बैंक 2023 में बाजारों को डॉलर और सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड निर्गमों के लिए खोलने वाला पहला भारतीय निर्गमकर्ता बना था। इसके बाद, इस बॉन्ड से प्राप्त आय से वित्तपोषित परियोजनाओं और आस्तियों के मूल्यांकन के बाद जुलाई 2023 में बैंक को 'एक्सटर्नल पोस्ट इश्यूंस रिब्यू' का दर्जा मिला। इस सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड के 'एक्सटर्नल पोस्ट इश्यूंस रिब्यू' का दर्जा मिलना इस बात का परिचायक है कि सभी परियोजनाओं की समीक्षा में पाया गया कि उनमें 'बॉन्ड की आय के उपयोग' से संबंधित मानदंडों का अनुपालन हुआ है और यह बैंक के पर्यावरणीय, सामाजिक गवर्नेंस (ईएसजी) फ्रेमवर्क में निर्धारित प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है। लंदन स्टॉक एक्सचेंज ने सम्यक जांच के बाद एक्जिम बैंक के सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड को अपने सस्टेनेबल बॉन्ड मार्केट (एसबीएम) प्लैटफॉर्म पर लिस्ट करने के लिए क्वालिफाई घोषित किया।

इंडिया एक्जिम बैंक का पूर्वानुमान, वित्तीय वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) में 111.2 बिलियन यूएस डॉलर का रहेगा भारत का मर्चेंडाइज निर्यात और 88.1 बिलियन यूएस डॉलर का रहेगा गैर-तेल निर्यात

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (इंडिया एक्जिम बैंक) ने वित्तीय वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही के लिए भारत के निर्यात पूर्वानुमान जारी कर दिए हैं। वित्तीय वर्ष

2024 की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) में, भारत के कुल मर्चेंडाइज निर्यात 111.2 बिलियन यूएस डॉलर और गैर-तेल निर्यात 88.1 बिलियन यूएस डॉलर के रहने का पूर्वानुमान है। मर्चेंडाइज निर्यात में जहां 6.3% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि का पूर्वानुमान है तो वहीं गैर-तेल निर्यात में 7.7% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि का अनुमान है। यह सकारात्मक वृद्धि वर्ष की प्रथम दो तिमाहियों में रही ऋणात्मक वृद्धि के बाद दर्ज की जा रही है। भारत के निर्यात में सकारात्मक वृद्धि, भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विकास दृष्टिकोण में सुधार और वैश्विक मौद्रिक नीति में नरमी के परिणामस्वरूप बढ़ती वैश्विक मांग के कारण हो सकती है। तथापि, यह परिदृश्य अन्य के साथ-साथ, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के संबंध में अनिश्चितताओं, भू-राजनीतिक झटकों और भू-आर्थिक फ्रेमवर्क जैसे जोखिमों पर निर्भर करता है।

उभरते वैश्विक व्यापार परिदृश्य में भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधों को मिला नया महत्त्व



ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में आयोजित एशियाई एक्जिम बैंक फोरम (ईबीएफ) की वार्षिक बैठक के दौरान 21 नवंबर, 2023 को इंडिया एक्जिम बैंक की प्रबंध निदेशक, सुश्री हर्षा बांगारी और एक्सपोर्ट फायनेंस ऑस्ट्रेलिया (ईएफए) के प्रबंध निदेशक और सीईओ, श्री जॉन हॉपकिन ने इंडिया एक्जिम बैंक के एक शोध अध्ययन का विमोचन किया। यह शोध अध्ययन 'संपर्कों को बढ़ावा देना: भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापार और निवेश संबंधों का आर्थिक विश्लेषण' शीर्षक से प्रकाशित किया गया है।

ईबीएफ की संकल्पना एशियाई निर्यात ऋण एजेंसियों के लिए संरचित तरीके से सूचनाओं के आदान-प्रदान और विचारों को साझा करने के उद्देश्य से 1996 में भारतीय निर्यात-आयात बैंक द्वारा की गई थी। एशियाई ईसीए फोरम का मुख्य कार्य क्षेत्रीय सहयोग को विकसित करना और बढ़ाना तथा एशियाई ईसीए समुदाय के भीतर दीर्घकालिक संबंध को बढ़ावा देने के लिए सदस्य संस्थाओं के बीच सुदृढ़ संबंध बनाना है। ईएफए ने 'निर्यात ऋण 2040: उभरते परिदृश्य के लिए भावी प्राथमिकताएं' विषय पर 28वीं ईबीएफ वार्षिक बैठकों की मेजबानी की। ■

विभिन्न देशों की आर्थिक स्थिति

सौजन्य: शोध एवं विश्लेषण समूह

श्रीलंका



श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में दो वर्षों के संकुचन के बाद 2024 में 5.4% की वृद्धि की उम्मीद है। 2025-28 में इसके लगभग 4% की औसत वृद्धि दर से बढ़ने का अनुमान है। उच्च बिजली दरों और मितव्ययी उपायों से निजी खपत पर दबाव पड़ेगा, जबकि सख्त मौद्रिक एवं वित्तीय नीति और राजनीतिक अनिश्चितता से निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तथापि, पर्यटन क्षेत्र के पुनरुद्धार और आयात प्रतिबंध हटने के कारण विनिर्माण क्षेत्र के विस्तार से आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी। तेल की कीमतों में कमी, स्थानीय मुद्रा की मजबूती और कमजोर घरेलू मांग के कारण 2024 में मुद्रास्फीति में औसतन 0.2% की कमी आने की संभावना है। हालांकि कुछ महीनों में अपस्फीति भी देखी गई। आईएमएफ कार्यक्रम और राजनीतिक माहौल की अनिश्चितता को देखते हुए श्रीलंकाई रुपये के 2024 के प्रारंभ में 1 यूएस डॉलर के मुकाबले 300 से अधिक और 2024 के अंत में 1 यूएस डॉलर के मुकाबले 310 श्रीलंकाई रुपये रहने का अनुमान है। 2024 में देश की अंतरराष्ट्रीय आरक्षित निधि में विभिन्न कारकों से बढ़ोत्तरी होने का अनुमान है। वस्तु व्यापार घाटा बढ़ने से चालू खाता शेष घाटे में रहेगा। तथापि, कमजोर घरेलू मांग, तेल की कीमतों में नरमी और मुद्रा में मजबूती से आयात बिल पर नियंत्रण रहेगा।

अल सल्वाडोर



अल सल्वाडोर की आर्थिक वृद्धि निरंतर उच्च मुद्रास्फीति, सख्त मौद्रिक नीति और इसके प्रमुख व्यापारिक भागीदारों में मंदी के कारण 2023 में 1.8% से 2024 में 2% तक मंदी रह सकती है। देश पर जीडीपी के 74% का भारी ऋण भार है और अगले दो वर्षों में इस भारी ऋण चुकौती का भुगतान करना है। सरकार अल्पकालिक बिलों में 2.8 बिलियन यूएस डॉलर के लगभग 1.4 बिलियन यूएस डॉलर (जीडीपी का 8%) को लक्ष्य करते हुए अल्पकालिक ऋण दायित्व के पुनर्वित्त पर ध्यान केंद्रित कर रही है। अल सल्वाडोर में 2001 से यूएस डॉलर चला आ रहा है। 2021 में इसने बिटकॉइन को दूसरी विधिमाम्य मुद्रा के रूप में पेश किया, जिससे क्रिप्टोकॉरंसी बाजारों की अस्थिर प्रकृति को देखते हुए वित्तीय क्षेत्र में अनिश्चितता पैदा हो गई (2021 से इसमें 30% से अधिक की गिरावट आई है)। क्रिप्टोकॉरंसी के प्रति सरकार के एक्सपोजर से दिवालियापन का जोखिम भी बढ़ गया है तथा डॉलरीकरण खतरा पैदा हो गया है। अल नीनो उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए काफी जोखिम पैदा करता है, जबकि मुद्रास्फीति में 2023 की 2.4% से 2024 में 1.5% तक कम होने का अनुमान है। चालू खाता घाटा 2022 के 6.6% से 2023 में जीडीपी का 4.5% न्यूनतर आंका गया। लेकिन संभावित भुगतान संतुलन का संकट बना हुआ है। बहुपक्षीय ऋण तक सीमित पहुंच पूंजी प्रवाह को बाधित कर सकती है और विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ सकता है।

जिबूती



जिबूती की अर्थव्यवस्था 2023 की 4.8% से बढ़कर 2024 में 5.5% और 2025 में 5.8% की दर से बढ़ने का अनुमान है। यह वृद्धि ट्रांसशिपमेंट और लॉजिस्टिक सेवाओं से निर्यात आय तथा बड़े पैमाने पर ऋण-वित्तपोषित निवेशों में बढ़ोत्तरी के कारण रहने के आसार हैं। अर्थव्यवस्था के लिए नकारात्मक जोखिमों में सेवा क्षेत्र पर निर्भरता, राजनीतिक संघर्ष, अधिकांश समुद्री व्यापार के लिए इथियोपिया पर निर्भरता तथा इथियोपिया के विकास में बाधाओं से होने वाले प्रभाव शामिल हैं। 2024 के मध्य में ईंधन सब्सिडी को हटाने के परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति की दर 2023 की 2.2% से बढ़कर 2024 में 2.5% हो जाएगी। तथापि, 2024-25 में 1 यूएस डॉलर के मुकाबले जिबूती फ्रैंक 177.7 के स्तर पर स्थिर रहने से 2025 में मुद्रास्फीति के गिरकर 1.8% तक रहने की संभावना है। इसके अलावा, 2024-25 में देश के विदेशी मुद्रा भंडार के मजबूत होने के बावजूद, इसका आयात कवर औसतन डेढ़ महीने नीचे रहने की आशंका है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानी जाने वाली सीमा से नीचे है। व्यापार अधिशेष कम करने के कारण चालू खाता अधिशेष 2023 के 15.9% से 2024 में घटकर 14.4% और 2025 में 11.6% होने का अनुमान है। कुल मिलाकर आयात और निर्यात में वृद्धि होगी, यद्यपि यह वृद्धि संभावित वृद्धि से कम होगी। जिबूती के सीमित एफडीआई आवक और कम विदेशी मुद्रा भंडार को देखते हुए ऋण संकट का जोखिम अधिक बना हुआ है।

लेबनान



बड़े पैमाने पर जमा निकासी और संप्रभु ऋण चूक के कारण लेबनान का आर्थिक संकट लगातार तीसरे वर्ष गहराता जा रहा है। वित्तीय क्षेत्र दिवालिया है और देश गंभीर वित्तीय एवं आर्थिक संकट से जूझ रहा है। अर्थव्यवस्था के 2023 में 2.6% के संकुचन के साथ 2024 में 2.1% की दर से बढ़ने का अनुमान है। लेबनान का ऋण की तुलना में जीडीपी अनुपात तीव्र मुद्रा अवमूल्यन के चलते तेजी से प्रभावित होता है, जिससे विदेशी मुद्रा ऋण का स्थानीय मुद्रा मूल्य बढ़ जाता है। 2019 में विदेशी मुद्रा ऋण, कुल ऋण का 40% था, जो संशोधित विनिमय दर अनुमानों के तहत 2023 में 90% से अधिक हो गया। जीडीपी की तुलना में सार्वजनिक ऋण 2020 में 236.5% पहुंच गया और 2023 में घटकर 197.9% रहा। आयात लागत में वृद्धि और आपूर्ति में व्यवधान के कारण लेबनानी पाउंड में नाटकीय उतार-चढ़ाव और पुनः मूल्य निर्धारण की संभावना बनी रहती हैं। लेबनान में कई विनिमय दरें प्रचलित हैं और आधिकारिक मूल्य एक यूएस डॉलर के मुकाबले 15,000 लेबनानी पाउंड है। 2023 में मुद्रा का अवमूल्यन 1 यूएस डॉलर के मुकाबले 87,291.6 लेबनानी पाउंड होने का अनुमान है। आयात लागत में वृद्धि के कारण 2023 में 222% की रिकॉर्ड उच्च मुद्रास्फीति रहने के आसार हैं। सीमित निर्यात आधार और आयातित इनपुट पर भारी निर्भरता के कारण लेबनान में 2023 में चालू खाता घाटा 22% दर्ज होने का अनुमान है। ■

मुद्राओं की स्थिति

सौजन्य: ट्रेजरी और लेखा समूह

इराकी दिनार

ID इराक की मुद्रा इराकी दिनार (आईक्यूडी) है, जिसे सेंट्रल बैंक ऑफ इराक (आईसीबी) द्वारा जारी किया गया है। 2020 के अंत में, एक राष्ट्रीय लिक्विडिटी संकट के कारण सेंट्रल बैंक ऑफ इराक (आईसीबी) ने यूएस डॉलर के मुकाबले इराकी दिनार (आईक्यूडी) का 22% अवमूल्यन कर दिया। इसका सार्वजनिक विरोध हुआ, लेकिन बाद में मूल्य वृद्धि के बीच, आईसीबी ने फरवरी 2023 में इराकी मंत्रिपरिषद की मंजूरी से विनिमय दर को 1,300 आईक्यूडी प्रति यूएस डॉलर पर बहाल कर दिया। इसके अलावा, वित्तीय अपराधों से निपटने और ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने के लिए इराक ने 1 जनवरी, 2024 से यूएस डॉलर में नकद निकासी और लेनदेन पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। हालांकि, जमाकर्ता 2023 के अंत तक जमा की गई राशि के लिए 2024 में यूएस डॉलर में निकासी कर सकेंगे और 2024 में किए गए डॉलर जमा को स्थानीय मुद्रा में आईक्यूडी 1,320 प्रति यूएस डॉलर की आधिकारिक दर पर निकाल सकेंगे।

आईसीबी ने धोखाधड़ी वाले लेनदेन को कम करने के लिए वायर ट्रांसफर को विनियमित करने हेतु अमेरिका के साथ मिलकर काम किया है। उसने सिटी बैंक और जेपी मॉर्गन सहित विदेशों के साथ समझौता किया, जिसका उद्देश्य दस इराकी बैंकों के लिए यूएस डॉलर आरक्षित निधि को बढ़ाना है। सरकार द्वारा अनुमोदित मुद्रा पुनर्मूल्यांकन के बावजूद, समानांतर बाजारों में दिनार के मूल्य के बारे में चिंताएं बनी हुई हैं, जो 2003 के अमेरिकी आक्रमण के बाद इराक की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के व्यापक प्रयासों को दर्शाती है। इसके अतिरिक्त, इराकी निजी बैंक अब अंतरराष्ट्रीय व्यापार लेनदेन की सुविधा के लिए यूएस डॉलर से परे यूरो, यूनाइटेड अरब अमीरात दिरहम, चीनी युवान और भारतीय रुपया जैसी विभिन्न विदेशी मुद्राओं का उपयोग करने के लिए अधिकृत हैं। तिमाही के दौरान यूएसडी/आईक्यूडी 1306-1309 की रेंज में रहा और 18 दिसंबर, 2023 को यूएसडी के मुकाबले आईक्यूडी 1308 पर बंद हुआ है।

स्विस फ्रैंक

CHF स्विस फ्रैंक (सीएचएफ) स्विट्जरलैंड और लिस्टेंस्टीन की विधिमान्य मुद्रा है। सीएचएफ का अर्थ है कॉन्फोएडरेटियो हेल्वेटिका फ्रैंक, जिसमें कॉन्फोएडरेटियो हेल्वेटिका स्विस परिषद का लैटिन नाम है। सीएचएफ को दुनिया की सबसे सुरक्षित आस्तियों में से एक माना जाता है और यह विदेशी मुद्रा बाजार में सबसे अधिक कारोबार वाली मुद्राओं में से एक है। डॉलर में कमजोरी के कारण स्विस फ्रैंक सितंबर 2023 में यूएसडी के मुकाबले 0.9244 के निचले स्तर से बढ़ गया है। भू-राजनीतिक तनाव बढ़ने, इज़राइल-हमास संघर्ष और निराशाजनक कॉर्पोरेट आय के कारण यह एक पसंदीदा सुरक्षित आश्रय स्थल बनता जा रहा है, और इस प्रकार, सरकारी बॉन्ड और येन जैसे पारंपरिक आश्रयों का आकर्षण कम हो रहा है। इसके अलावा, यूरो के मुकाबले फ्रैंक का मूल्य सितंबर 2022 में 0.9409 पहुंच गया, जो जनवरी 2015 में स्विस नेशनल बैंक (एसएलबी) द्वारा यूरो के मुकाबले इसका उच्चतम स्तर है।

इसके अतिरिक्त, एसएनबी ने विदेशी मुद्रा भंडार को बेचकर फ्रैंक को मजबूत करना जारी रखा, जिससे अस्थिर कमोडिटी कीमतों से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके और आयात मुद्रास्फीति को सीमित किया जा सके, जो यूरोप में उच्च मूल्य वृद्धि के मुकाबले केंद्रीय बैंक के प्रमुख हथियारों में से एक है। परिणामस्वरूप, एसएनबी द्वारा रखा गया विदेशी मुद्रा भंडार नवंबर में लगातार छठे महीने गिरकर सात वर्षों में सबसे कम सीएचएफ 641.73 बिलियन पर आ गया। दिसंबर की हालिया पॉलिसी बैठक में, स्विस नेशनल बैंक ने ब्याज दर को 1.75% पर अपरिवर्तित रखा। तिमाही के दौरान, यूएसडी की तुलना में सीएचएफ 0.8591-0.9244 के बीच रहा और 19 दिसंबर, 2023 को 0.8608 पर बंद हुआ।

इजरायली शेकेल

NIS नई इजरायली शेकेल (आईएलएस) इजरायल की मुद्रा है और इसका उपयोग वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी के फिलिस्तीनी क्षेत्रों में विधिमान्य मुद्रा के रूप में भी किया जाता है। नई शेकेल 100 एगोरोट में विभाजित है। नई शेकेल 01 जनवरी, 1986 से उपयोग में है, जब इसे 1000:1 के अनुपात में अत्यधिक मुद्रास्फीति वाले पुराने शेकेल के स्थान पर शुरू किया गया था। अक्टूबर 2023 में, बैंक ऑफ इजरायल ने गाजा में फिलिस्तीनी उग्रवादियों के साथ चल रहे संघर्ष के बीच स्थिरता बनाए रखने के लिए 30 बिलियन यूएस डॉलर तक की विदेशी मुद्रा की अपनी पहली बिक्री की घोषणा की थी। यह निर्णय अभूतपूर्व सुरक्षा स्थिति के कारण लिया गया, जिसके कारण डॉलर के मुकाबले शेकेल 2.8% गिर गया। राजनीतिक उथल-पुथल के कारण 2023 में शेकेल पहले से ही 10% कमजोर हो चुका था, और गाजा में हमास के साथ लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष के चलते और अवमूल्यन हो गया। इजरायल-हमास में जारी संघर्ष के बीच इजरायली शेकेल डॉलर के मुकाबले 4.0273 के रिकॉर्ड स्तर तक नीचे गिर गया, जो पिछले 11 वर्षों में निम्नतम स्तर है।

इसके अलावा, बैंक ऑफ इजरायल ने संघर्ष के दौरान शेकेल की गिरावट को रोकने के लिए अक्टूबर में 8.2 बिलियन यूएस डॉलर की विदेशी मुद्रा बेची। परिणामस्वरूप, डॉलर के मुकाबले शेकेल 1% से अधिक की मजबूती से लगभग 3.84 के स्तर पर पहुंच गया। इन मध्यवर्ती उपायों के परिणामस्वरूप देश की विदेशी आरक्षित मुद्रा अक्टूबर के अंत में 191.2 बिलियन यूएस डॉलर से कम हो गई, जो देश के जीडीपी के 36.8% के साथ वर्ष का निम्नतम स्तर रहा।

तिमाही के दौरान, नई इजरायली शेकेल मुद्रा 23 अक्टूबर, 2023 के 4.0855 के निचले स्तर से बढ़कर यथा 19 दिसंबर, 2023 को 3.6357 तक पहुंच गई और 19 दिसंबर, 2023 को 3.6467 पर बंद हुई।

कनाडाई डॉलर

C\$ कनाडाई डॉलर (सीएडी) दुनिया की 7वीं सबसे कारोबार वाली मुद्रा है। यह यूएस डॉलर, यूरो, येन, स्टर्लिंग और रेनमिनबी के बाद दुनिया की छठी सबसे अधिक आरक्षित मुद्रा भी है।

कनाडा की जीडीपी वृद्धि दर 1.1% है, जो अमेरिका की 5.2% दर के मुकाबले काफी कम है। इसका मुख्य कारण अंतरराष्ट्रीय व्यापार चुनौतियां और कम इन्वेंट्री होना है। हालांकि सार्वजनिक खर्च ने घरेलू मांग को बढ़ा दिया है और सरकारी गतिविधि में 0.4% का संकुचन देखने को मिला है। इसके अतिरिक्त, बैंक ऑफ कनाडा (बीओसी) ने अपने ओवरनाइट लक्ष्य को 5.0% पर बनाए रखा है, जो आगे और सख्ती के प्रति अनिच्छा का संकेत है। हॉकिश पूर्वाग्रह बनाए रखते हुए, बीओसी ने स्वीकार किया कि अर्थव्यवस्था में "अब अधिक मांग नहीं है।"

नवंबर 2023 की शुरुआत में, कनाडा की बेरोजगारी दर 5.5% से बढ़कर 5.7% हो जाने के बाद कनाडाई पर डॉलर दबाव बढ़ गया। इसके बाद कनाडाई डॉलर यूएस डॉलर के मुकाबले 1.39 से 1.35 तक मजबूत हो गया है, जो तेल की गिरती कीमतों और यूएस की तुलना में बढ़ती व्यापक नकारात्मक ब्याज दर के बावजूद दो महीने में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। विश्लेषक कनाडाई डॉलर के लिए तेजी का पूर्वानुमान बनाए हुए हैं। उनका मानना है कि इसका मूल्य कम आंका गया तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सुदृढ़ आर्थिक संबंधों से यह लाभ लेने के लिए तैयार है। 19 दिसंबर, 2023 को यूएसडी/सीएडी की क्लोजिंग रेट 1.3331 थी। ■

एक्जिम मित्र

सौजन्य: एक्जिम मित्र समूह

भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने और भारतीय उद्यमियों के बीच व्यापार वित्त, ऋण बीमा और व्यापार से जुड़ी अन्य जानकारी के प्रसार की विषमता को दूर करने के लिए इंडिया एक्जिम बैंक ने एक पोर्टल तैयार किया है। इसके मुख्य रूप से दो उद्देश्य हैं। निर्यात के लिए ऋण उपलब्धता के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराना और व्यापार से संबंधित सूचनाएं प्रदान करना। एक्जिम मित्र के जरिए ऐसे प्रयास करना, जिनसे भारतीय उद्यमियों की अंतरराष्ट्रीय व्यापार से जुड़ी जिज्ञासाओं का समाधान हो। इनमें से कुछ को नीचे दिया गया है:

भारत से न्यूजीलैंड को टमाटर के निर्यात के लिए प्रक्रियाओं और फाइटोसैनिटरी अनुपालन पर जानकारी

भारत से न्यूजीलैंड को टमाटर निर्यात करने के लिए जैव सुरक्षा आयात परमिट प्राप्त करने जैसे विशिष्ट विनियमों और प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता है। यह परमिट न्यूजीलैंड के प्राथमिक उद्योग मंत्रालय (एमपीआई) द्वारा ताजा टमाटरों के आयात के लिए जारी किया जाता है। एमपीआई की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसके अलावा भारत में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, विशेष रूप से राष्ट्रीय वनस्पति संरक्षण संगठन (एनपीपीओ) से फाइटोसैनिटरी प्रमाणपत्र प्राप्त करना होता है। यह प्रमाणपत्र सत्यापित करता है कि टमाटर न्यूजीलैंड के आयात स्वास्थ्य मानकों को पूरा करते हैं या नहीं। मौसम और संभावित कीट जोखिमों के आधार पर टमाटर के लिए आवश्यक विशिष्ट उपचारों को चिह्नित करने के लिए कोई भी व्यक्ति एमपीआई वेबसाइट से परामर्श विकल्प का उपयोग कर सकता है। उपायों और प्रक्रियाओं के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया निम्नलिखित उपयोगी लिंक पर जाएं-

- प्राथमिक उद्योग मंत्रालय न्यूजीलैंड (एमपीआई): <https://www.mpi.govt.nz/import/>
- जैव सुरक्षा आयात परमिट: <https://www.mpi.govt.nz/import/>
- राष्ट्रीय वनस्पति संरक्षण संगठन (एनपीपीओ) भारत: <https://ppqs.gov.in/>
- भारतीय निर्यात संगठन महासंघ (एफआईओ): <https://fieo.org/>

निर्यात व्यवसाय में प्री-शिपमेंट और पोस्ट-शिपमेंट ऋण से संबंधित जानकारी

अंतरराष्ट्रीय व्यापार में प्री-शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट ऋण के रूप में वित्तपोषण के दो विकल्प उपलब्ध हैं। इनके जरिए खरीदारों से वस्तु उत्पादन/खरीदी और भुगतान प्राप्त करने के बीच के अंतर को कम किया जाता है। ये विकल्प कच्चे माल, विनिर्माण, प्रसंस्करण, पैकेजिंग और अन्य प्री-शिपमेंट लागत जैसे खर्चों के लिए उपयोगी हैं। यह ऋण सामान्यतया, बैंकों द्वारा पैकेजिंग क्रेडिट या कार्यशील पूंजी ऋण के रूप में प्रदान किया जाता है। यह निर्यातक को भुगतान की प्रतीक्षा किए बिना उत्पादन शुरू करने में मदद करता और उनके लिए वित्तीय जोखिम को कम करता है। इसे वस्तु या निर्यातक की अन्य आस्तियों द्वारा प्रतिभूतित किया जा सकता है। पोस्ट-शिपमेंट ऋण, वस्तुओं को भेजे जाने के बाद, लेकिन खरीदार से भुगतान प्राप्त होने से पहले वित्तपोषण प्रदान करता है। यह भुगतान आने तक परिवहन, बीमा, कस्टम्स क्लियरेंस और कार्यशील पूंजी जरूरतों जैसे खर्चों को कवर करने के लिए उपयोगी है। यह ऋण सामान्यतया, बैंकों द्वारा बिल डिस्काउंटिंग या निर्यात प्राप्य वित्त के रूप में प्रदान किया जाता है। यह खरीदार द्वारा भुगतान न किए जाने के जोखिम को कम करता है। क्योंकि बैंक निर्यात दस्तावेजों के आधार पर अग्रिम निधि प्रदान करता है और इसे निर्यात दस्तावेजों या निर्यातक की अन्य आस्तियों से इसे प्रतिभूतित किया जा सकता है।

राज्य एवं केंद्रीय करों और शुल्कों में छूट (आरओएससीटीएल) योजना से संबंधित जानकारी

आरओएससीटीएल योजना एक सरकारी पहल है, जो भारत से निर्यात किए जाने वाली वस्तुओं पर अंतर्निहित राज्य एवं केंद्रीय करों और शुल्कों की प्रतिपूर्ति कर निर्यात को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन की गई है।

पात्रता:

- यह योजना सीमा शुल्क के अध्याय 61, 62 और 63 के अंतर्गत निर्यातों पर लागू होती है, जिसमें टेक्सटाइल्स, गारमेंट और निर्मित उत्पाद शामिल हैं।
- आपका डीजीएफटी में पंजीकृत आईईसी धारक होना आवश्यक है।

योजना के लिए आवेदन कैसे करें:

- **योजना के लिए पंजीकरण करें:** डीजीएफटी के ऑनलाइन पोर्टल (<https://www.dgft.gov.in/>) पर लॉग इन करें और आरओएससीटीएल योजना के लिए अपनी फर्म को पंजीकृत करें।
- **शिपिंग बिल फाइल करें:** अपने निर्यात शिपमेंट के लिए शिपिंग बिल तैयार करें और सीमा शुल्क विभाग में फाइल करें। सुनिश्चित करें कि सभी विवरण सटीक और पूर्ण हैं।
- **आरओएससीटीएल ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप का दावा:** कस्टम्स क्लियरेंस के बाद, डीजीएफटी पोर्टल पर आरओएससीटीएल ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप के लिए ऑनलाइन आवेदन करें। शिपिंग बिल, चालान और पैकेजिंग सूची जैसे सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
- **सत्यापन और संवितरण:** डीजीएफटी आपके आवेदन और दस्तावेजों का सत्यापन करता है। यदि स्वीकृति मिल जाती है, तो 15 दिनों के भीतर आपके नामित बैंक खाते में आरओएससीटीएल ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी कर दी जाती है।
- **स्क्रिप का उपयोग:** आप शुल्क-मुक्त इनपुट के आयात या बाद के निर्यात पर सीमा शुल्क के भुगतान के लिए ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप का उपयोग कर सकते हैं। इसे अन्य निर्यातकों को हस्तांतरित या बेचा भी जा सकता है।

प्याज व्यापार में कोटेशन, खरीदार, मूल्य निर्धारण मार्जिन और दस्तावेजीकरण के बारे में जानकारी

एक्जिम मित्र पोर्टल के निर्यात-आयात की जानकारी खंड के अंतर्गत "निर्यात के लिए शुरुआती कदम" का संदर्भ लिया जा सकता है, जहां मूल्य निर्धारण और लागत निर्धारण पर एक खंड है। चूंकि प्याज की कीमतों में उतार-चढ़ाव होता रहता है, इसलिए कोटेशन का निर्धारण करते समय, निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है:

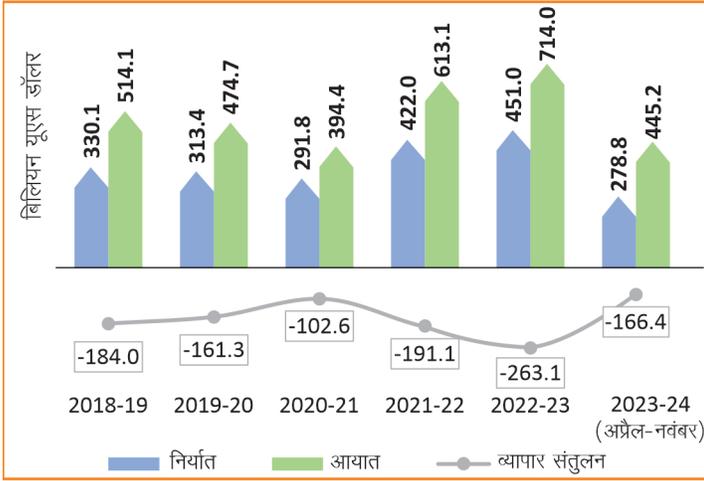
- मात्रा
- डिलीवरी की अवधि
- उत्पाद की कीमत
- माल ढुलाई की लागत
- भुगतान की शर्तें
- पैकेजिंग
- वित्तपोषण की लागत
- कोई अन्य व्यय आदि।

इच्छुक व्यक्ति निर्यात लागत और मूल्य निर्धारण, निर्यात दस्तावेजीकरण और प्रक्रियाओं की विस्तृत जानकारी और एपीडा द्वारा उनके एग्री एक्सचेंज, रेडी रेकनर पेज https://agriexchange.apeda.gov.in/Ready%20Reckoner/Essential_Exporting.aspx# पर दी गई प्याज के निर्यात के बारे में विशेष जानकारी देख सकते हैं।

आंकड़ों में भारतीय अर्थव्यवस्था

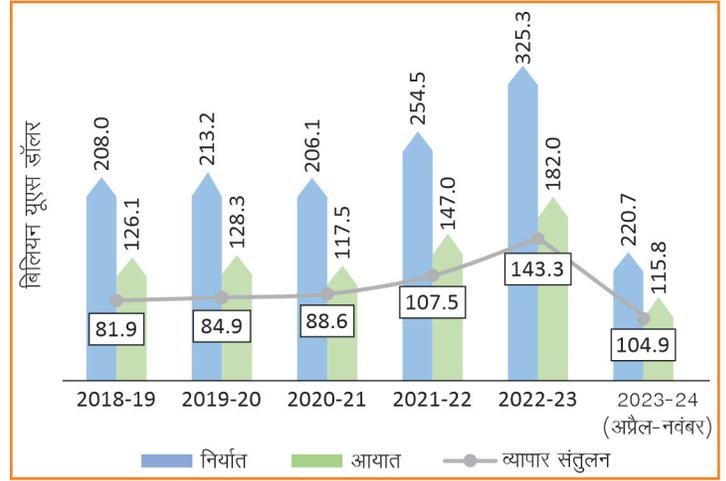
सौजन्य: शोध एवं विश्लेषण समूह

वस्तु व्यापार



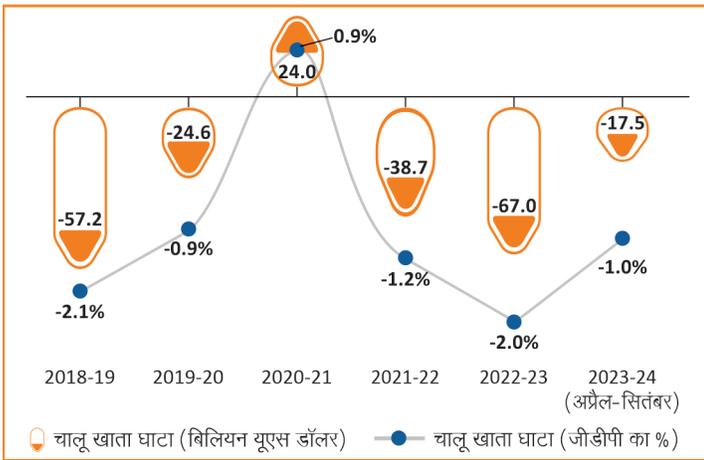
स्रोत: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

सेवाएं व्यापार



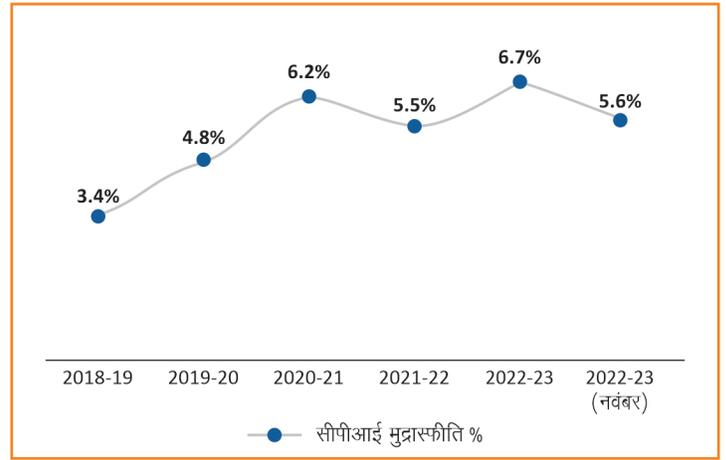
स्रोत: आरबीआई

चालू खाता घाटा



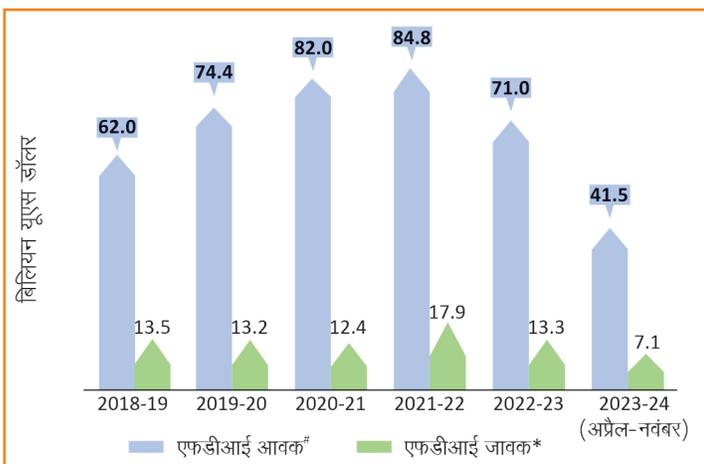
स्रोत: आरबीआई

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई)



स्रोत: सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

प्रत्यक्ष विदेशी मुद्रा निवेश का प्रवाह

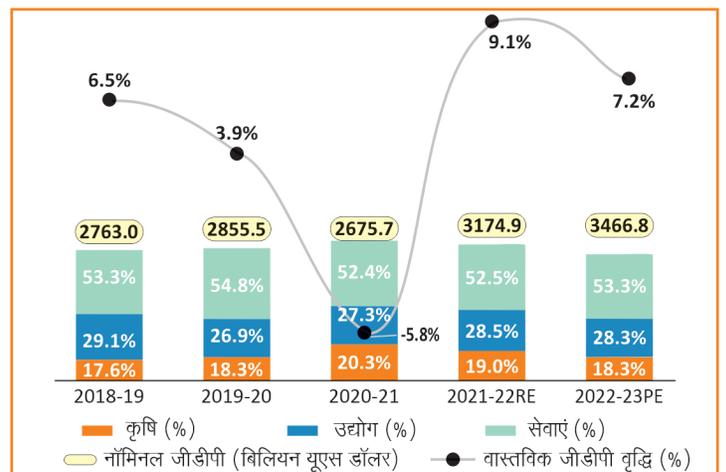


नोट: * एफडीआई जावक वास्तविक आंकड़े दर्शाते हैं और इसमें इक्विटी, ऋण, इन्वोक की गारंटियां शामिल हैं।

"एफडीआई आवक में इक्विटी, पुनर्निवेश आय और अन्य पूंजी शामिल हैं।

स्रोत: आरबीआई और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

क्षेत्रवार उत्पादन



नोट: पीले रंग के आंकड़े नॉमिनल जीडीपी (बिलियन यूएस डॉलर) को दर्शाते हैं ;

आरई- संशोधित अनुमान ; पीई- अंतिम अनुमान

स्रोत: अंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थान एवं सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार